



प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी चौड़ावत

RNI No. MPIN/2018/76422

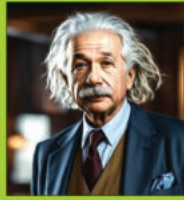
माहि की गूँज

बेबाकी के साथ.. सच

www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

जिस
व्यक्ति
ने
कभी
गलती



नहीं की, उसने कभी कुछ
नया करने की कोशिश
नहीं की।

अल्बर्ट आइंस्टीन

वर्ष-08, अंक - 51 (साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 08 अक्टूबर 2026

पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

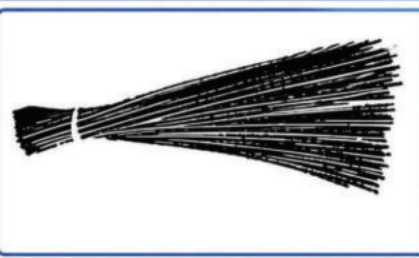
क्या झाबुआ जिले की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है...?

माहि की गूँज, झाबुआ।

संजय भट्टेवरा

झाबुआ जिला आमतौर पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है। 2003 के विधानसभा चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दे तो अधिकांश समय यहाँ कांग्रेस का पलड़ा ही भारी रहा। यही नहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव जीता लेकिन महज डेढ़ साल में ही सांसद दिलीप सिंह जी भूरिया के निधन के पश्चात हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ने वापसी की। वो वापसी इसलिए भी खास थी कि, तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 50 से ज्यादा सभाएं की थी और बावजूद इसके भाजपा प्रत्याशी निर्मला भूरिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ भाजपा प्रत्याशी निर्मला भूरिया को उनके पिता के निधन के बाद भी सहानुभूति का लाभ नहीं मिला था। इस हार के पश्चात तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि, झाबुआ जिला परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यही नहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जब प्रदेश में भाजपा ने 230 में से 166 सीटें जीती थीं तब भी जिले की तीन में से दो सीटें कांग्रेस ने जीतकर यह साबित किया था। जिले में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं लेकिन 2026 के जिला पंचायत के वार्ड चुनाव में आम जनता ने कांग्रेस और भाजपा समर्थित दोनों ही दलों के प्रत्याशी को नकारते हुए तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगानंद को चुना। जिसके बाद यह चर्चा जोरो पर है कि

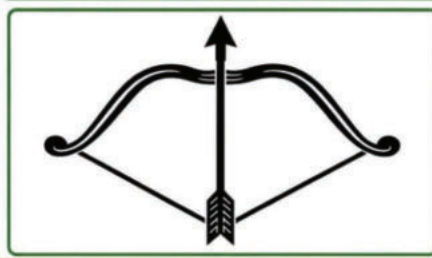
आम आदमी पार्टी



क्या झाबुआ जिले का अगला चुनावी तिसरा विकल्प यह रह सकते हैं...

क्या झाबुआ जिले की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है...? अतीत में अगर देखें तो यहाँ कलसिंह भाभर निर्दलीय रूप से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वह जीत कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीत के रूप में देखी गई है थी। वहीं पिछले जिला पंचायत के चुनाव में भी वार्ड नंबर 9 में जयसमर्थित रेखा निनामा ने अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज की थी। तब भी यही कहा जा रहा था कि, जिले में जनता कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य तीसरे विकल्प की तलाश में है। हालांकि रेखा निनामा के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने यह सीट पुनः प्राप्त कर ली जिसके बाद अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव के परिणामों ने एक बार फिर इन अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि यह उपचुनाव गैर दलीय आधार पर हुए थे लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ा था। बकायदा अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया

भारतीय आदिवासी पार्टी



था और जोर-शोर से चुनाव प्रचार भी किया गया था। भाजपा ने 23 पंचायतों के लिए 23 प्रभारी तक नियुक्त किए थे लेकिन बावजूद इसके जनता से दोनों ही प्रमुख दलों के दावे को नकारते हुए तीसरे विकल्प को चुना। जो कि दोनों ही दलों के लिए खतरे की घंटी है। इस आम चुनाव के परिणामों का असर वर्तमान राजनीति पर भले ही न पड़े लेकिन इसका असर आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव व विधानसभा चुनाव पर पड़ना निश्चित है। दोनों ही दलों के लिए यह परिणाम आत्मचिंतन का विषय अवश्य ही है। विशेष रूप से कांग्रेस के लिए यह चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय था क्योंकि इस वार्ड में उसके दो प्रतिष्ठित नेताओं पूर्व केंद्रीय मंत्री कालिलाल भूरिया तथा वर्तमान विधायक डॉ. विक्रान्त भूरिया की गृह पंचायत का क्षेत्र भी था। लेकिन कांग्रेस इन वरिष्ठ नेताओं की ग्रह पंचायत में भी बढ़त नहीं ले सकी जो कि उसके लिए चिंतनीय है कि आखिर चुक कहाँ हुई।

वहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि पार्टी, केंद्र और राज्य में सत्ताधीश है और उपचुनाव में प्रचार के लिए नेताओं की फौज तैनात कर दी थी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया का भी ग्रह क्षेत्र था बावजूद इसके भाजपा यह सीट नहीं जीत पाई। जिसके बाद आम जनता का कहना है कि, चुनाव में नेता नहीं कार्यकर्ता वोट दिलाते हैं अब जबकि उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं दोनों ही दलों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आम जनता दोनों ही प्रमुख पार्टियों को आजमाने के बाद अब तीसरे विकल्प की ओर आशा-भरी निगाहों से देख रही है। जो परंपरागत राजनीति से हटकर आम जनता के मुहों पर जनता के साथ खड़ी रहे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगानंद के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वे जरूरत के समय आम जनता के साथ खड़े होते हैं। हालांकि महज एक उपचुनाव के परिणाम के आधार पर आगामी राजनीति या जनता के मूड का आकलन करना कठिन है। लेकिन फिर भी आम जनता ने अपना फैसला सुना कर दोनों ही दलों को आत्मचिंतन का अवसर अवश्य दिया है। अब देखना ये है कि, दोनों प्रमुख दल इस परिणाम का उपयोग अपनी गलतियाँ सुधारने में करते हैं या इसे महज इफतेकाफ समझकर अपने पुराने राजनीति दरे पर ही चलकर आगामी चुनाव में उतरते हैं...?

बहरहाल इस उपचुनाव के एक परिणाम ने कई संदेश देकर दोनों ही दलों को चौकन्ना अवश्य कर दिया है और यह भी साबित कर दिया है कि, राजनीति में किसी को भी कमजोर आंकने की भूल नहीं करना चाहिए। राजनीति में कौन कब और किसको मात दे दे कहाँ नहीं जा सकता है।

25 साल की जिम्मेदारी पूरी होने पर मोदी बोले महत्वाकांक्षा नहीं, मिशन के लिए जीता हूँ

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के प्रमुख की जिम्मेदारी संभालते हुए 25 वर्ष पूरे किए। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। मोदी ने कहा कि,



उन्होंने कभी किसी पद को लक्ष्य बनाकर काम नहीं किया, बल्कि देशसेवा को मिशन मानकर काम किया है।

मोदी ने कहा कि जीवन की हर घटना ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। जिसने गिराया, उसी ने दोबारा खड़ा होना सिखाया और विरोध ने लोकतंत्र की शक्ति समझाई। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का अनुभव और जनता का विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की है।

अपने छत्र जीवन को याद करते हुए मोदी ने कहा कि वडनगर के स्कूल में सीखने की जो ललक बनी, वह आज भी कायम है और वह स्वयं को विद्यार्थी मानते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान अभियान ने असफलता से उबरकर आगे बढ़ना सिखाया, जबकि कोरोना महामारी ने एकजुटता का महत्व समझाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और देश की सेवा उनका दायित्व है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। उन्होंने इस यात्रा को जनता के आशीर्वाद का परिणाम बताते हुए भविष्य में भी सामूहिक प्रयासों से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया।

साढ़े तीन साल बाद बढ़ी रेपो दर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने

लगातार बढ़ रही खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए साढ़े तीन साल बाद रेपो दर में बढ़ोतरी की है। बुधवार को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया। इसके बाद रेपो दर 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गई है। फरवरी 2023 के बाद यह पहली बार है, जब रेपो दर में बढ़ोतरी की गई है।

रेपो दर बढ़ने से गृह ऋण, वाहन ऋण सहित अन्य खुदरा कर्ज की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर मकान और वाहन खरीदने वाले लोगों पर पड़ेगा। वर्तमान में अधिकांश बैंकों की ब्याज दरें रेपो दर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद कर्ज महंगा होने की संभावना है।

आईआईटी बॉम्बे में नकल के आरोप पर सीधे कार्रवाई नहीं

मुंबई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे छात्रों पर पढ़ाई के दबाव और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए परीक्षा संबंधी अनुशासनात्मक नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। संस्थान ने परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल के आरोपों पर सीधे कार्रवाई करने के बजाय पहले छात्र का पक्ष सुनने और उसे मार्गदर्शन देने के लिए नई मानक कार्यप्रणाली का मसौदा तैयार किया है।



यह मसौदा बीटक छात्र सहित वाकोंडे की 18 सितंबर को आत्महत्या के बाद तैयार किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत परीक्षा में गड़बड़ी के संदेह में पकड़े गए छात्र को अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले मार्गदर्शक शिक्षक या विभागाध्यक्ष से बातचीत की अवसर दिया जा सकता है। संस्थान का उद्देश्य छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव कम करना और उन्हें यह समझाना है कि परीक्षा में

नए नियमों में परीक्षा निरीक्षकों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने का प्रस्ताव है। इसमें नकल के संदिग्ध मामले में उठाए जाने वाले कदम, दर्ज किए जाने वाले तथ्यों और छात्र के साथ व्यवहार की प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। साथ ही छात्र पर अनुचित दबाव डालने या उससे जबरन माफीनामा लिखवाने से बचने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं, सौरव दास ने पूछा पुलिस कौन होती है?

नई दिल्ली, एजेंसी।

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प. स्त। वि. त. प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति नहीं मिली है। पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास बुधवार को संसद मार्ग थाने पहुंचे और प्रदर्शन की औपचारिक सूचना पुलिस को दी। हालांकि, पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया।



सौरव दास ने कहा कि पुलिस को पहले ही प्रदर्शन की सूचना इसलिए पुलिस का पूरा सहयोग करेंगी। पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर दास ने सवाल उठाया कि जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पुलिस की अनुमति क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि भूमिका प्रदर्शन की अनुमति देने या रोकने के बजाय प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था संभालने की होनी चाहिए।

दी गई है, ताकि बाद में यह नहीं कहा जा सके कि पुलिस को कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगी

और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में

पुलिस का पूरा सहयोग करेंगी। पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर दास ने सवाल उठाया कि जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पुलिस की अनुमति क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि भूमिका प्रदर्शन की अनुमति देने या रोकने के बजाय प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था संभालने की होनी चाहिए।

एसआईआर में नाम हटाने के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाए जाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग ने कहा कि 13.39 करोड़ मतदाताओं के नाम सीधे तौर पर मतदाता सूची से नहीं हटाए गए हैं, बल्कि सत्यापन के दौरान उन्हें अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और दोहरा पंजीकरण वाली श्रेणियों में चिह्नित किया गया है। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है।

चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तीन चरणों में कुल 95.40 करोड़ मतदाताओं का भौतिक और डिजिटल सत्यापन किया गया। इस दौरान 13.39 करोड़ मतदाता संबंधित श्रेणियों में आए गए। इनमें 3.01 करोड़ मतदाता ऐसे थे, जो अपने पते पर नहीं मिले या जिनका कोई पता नहीं चल सका। वहीं 6.30 करोड़ मतदाता ऐसे आए गए, जो अपना पुराना घर या शहर स्थायी रूप से छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। इसके अलावा 2.80 करोड़ मृत मतदाताओं और 1.02 करोड़ ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई,

जिनके नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या क्षेत्रों में दर्ज थे। करीब 26 लाख नाम अन्य तकनीकी और प्रक्रियात्मक श्रेणियों में रखे गए। इस तरह कुल 13.39 करोड़ मतदाताओं को संबंधित श्रेणियों में चिह्नित किया गया। आयोग के अनुसार मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया मनमाने तरीके से नहीं की गई। देशभर में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। इसके बाद तैयार सूची राजनीतिक दलों के 22 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्तरीय प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रवार

उपलब्ध कराई गई, ताकि वे भी सूची का मिलान और जांच कर सकें। आयोग ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद आम लोगों और पात्र मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने तथा गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से सूची में शामिल नहीं हो पाया है तो उसके लिए दावा और आपत्ति की प्रक्रिया उपलब्ध है। पात्र नागरिक निर्धारित प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि

अंतिम मतदाता सूची में भी नाम शामिल नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति जिला दंडाधिकारी या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वैधानिक अपील कर सकता है।

आयोग ने कहा कि 13.39 करोड़ की संख्या को मतदाताओं के अधिकार समाप्त किए जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह मतदाता सूची के सत्यापन और उसे अद्यतन करने की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र मतदाता को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

राहुल-प्रियंका समेत कई विपक्षी सांसदों पर एफआईआर

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर जबरन प्रवेश करने के मामले में लोकसभा में



नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इंडिया गठबंधन के कई सांसदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विपक्षी नेताओं के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मामला मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन से जुड़ा है। विपक्षी सांसद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की थी।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। इसके बाद विपक्षी नेता सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को पुलिस बैरिकेड पर चढ़ते हुए देखा गया। पुलिस के रोकने के बावजूद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य प्रदर्शनकारी स्वागत द्वार से आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश कर गए।

इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को आकाशवाणी भवन तथा नीति आयोग कार्यालय के पास संसद मार्ग पर रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच काफी देर तक गतिरोध बना रहा।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट किया था कि आकाशवाणी भवन परिसर में रातभर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और परिसर खाली करने को कहा था। परिसर खाली नहीं करने पर हिरासत में लेने की चेतावनी भी दी गई। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि, कुछ घंटे बाद सभी को रिहा कर दिया गया।

मतदाता सूची विवादः

सत्ता-विपक्ष आमने-सामने



नई दिल्ली, एजेंसी।

चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का पुराना संसद भाषण साझा कर विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाए। रिजिजू ने दावा किया कि सिब्बल के पुराने भाषण से कांग्रेस के मौजूदा आरोपों पर सवाल खड़े होते हैं।

वीडियो में सिब्बल मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर कहते दिखाई दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित होने, मृत्यु होने या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने की स्थिति में नाम हटाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम सूची से हट गया हो तो वह निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर दोबारा नाम दर्ज कराने का अनुरोध कर सकता है।

रिजिजू ने इसी पुराने बयान को साझा करते हुए विपक्ष के मौजूदा विरोध पर सवाल उठाया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है।

12 लाख से अधिक की लागत से बना शासकीय उचित मूल्य दुकान का गोदाम अब भी अधूरा

सरकारी भवन होने के बावजूद निजी घर से हो रहा दुकान का संचालन, ग्रामीणों ने उठाए सवाल

माही की गूंज, खवासा।

ग्राम पंचायत परवाड़ा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के लिए 12 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा गोदाम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन सरकारी भवन में होने के बजाय निजी घर से किया जा रहा है। ऐसे में शासन द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे भवन का उद्देश्य ही सवाल के घेरे में नजर आ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि, शासन की राशि खर्च कर यदि उचित मूल्य दुकान के लिए भवन तैयार किया गया है तो उसका उपयोग सार्वजनिक हित में होना चाहिए। लेकिन भवन का निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अभी भी उचित मूल्य की दुकान के लिए निजी मकान का रुख करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है।

लोगों से मिली जानकारी अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन, दुकान संचालक द्वारा अपने निजी घर से किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि, जब शासन ने दुकान के लिए अलग भवन निर्माण की स्वीकृति देकर लाखों रुपए खर्च किए हैं तो फिर दुकान का संचालन सरकारी भवन में क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर निर्माण कार्य पूरा कराने और सरकारी भवन को उपयोग में लाने की जिम्मेदारी किसकी है?



शासकीय उचित मूल्य का अधूरा भवन।

लाखों खर्च के बाद भी भवन का लाभ नहीं

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बड़ी राशि खर्च की जाती है, लेकिन समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने तथा भवनों का उपयोग शुरू नहीं होने से योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। परवाड़ा में भी ऐसा ही मामला सामने आने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है।

परवाड़ा पंचायत के लोगों का कहना है कि, संबंधित

विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन भवन की स्थिति का निरीक्षण करें और अधूरे पड़े गोदाम का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन उसी भवन से शुरू करवाया जाए।

भवन बनने से लेकर अब तक कई तरह की कमियां दिख रही हैं, भवन में अभी से ही सरिया दिखाई दे रहे हैं, तो माल मटेरियल का भी सही उपयोग नहीं हुआ।

जो भवन बनाया गया है, उसमें कई तरह की

अनियमितता सामने दिखाई दे रही है। शुरूआती भवन निर्माण के कार्य से ही इसमें कमियां नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार सब इंजीनियर ने इस और कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने इस और देखना उचित नहीं समझा। और ठेकेदार ने अपने मनमर्जी अनुसार कार्य किया। जिससे यह भवन बनने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।

वही ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण होते हैं उसकी देखरेख करने के लिए सिविल इंजीनियर के साथ असोसिएट इंजीनियर की भी जिम्मेदारी होती है कि वह भी इस और ध्यान दें। लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं की सब मिलकर बंदर बाट कर रहे हैं? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि, पूरे मामले की जांच कर भवन निर्माण की वास्तविक स्थिति, खर्च हुई राशि तथा दुकान संचालन की व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक की जाए और यदि कहीं लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

मामले में सिविल इंजीनियर नवलसिंग बड़ोले से चर्चा की तो बताया, मुझे आए हुए सालभर हुआ है और उसकी एक किस्त ही जारी हुई है, दूसरी किस्त अभी मिली नहीं है। इसलिए कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जैसे ही दूसरी किस्त जमा होती है तो हमारे द्वारा कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

विद्यार्थी खुद भी बेस्ट बनें-साबनानी

माही की गूंज, सारंगी।

पुलिस चौकी सारंगी और शासकीय विद्यालय सारंगी के संयुक्त तत्वावधान में सेवा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओपी सुश्री अनुरक्ति साबनानी उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए प्रेरणादायक बातें कहीं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के सूत्र दिए।



विद्यार्थियों से संवाद करते हुए मुख्य अतिथि सुश्री अनुरक्ति साबनानी ने कहा कि, छात्र-जीवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्वर्णकाल है, इसलिए हर विद्यार्थी खुद भी बेस्ट बनें और अपने साथी को भी बेस्ट बनाएं की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समानता के वास्तविक अर्थ को समझते हुए उन्होंने कहा कि, समानता का अधिकार यह है कि जिसको जितनी जरूरत है, उसे उतना मिले।

अपराध नियंत्रण को पुलिस का मुख्य कर्तव्य बताते हुए उन्होंने बच्चों को कानून की बुनियादी जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं और बालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोई भी आपके या आपकी सहेली के साथ गलत करे, तो बिना डरे उसकी सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को गुडच-बैडच, सायबर सुरक्षा, और नशामुक्ति के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जागरूक किया। संबोधन के अंत में बच्चों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी एसडीओपी द्वारा दिए गए।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु कलेक्टर की अपील

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक जिले के मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा फॉर्म-6 के माध्यम से नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि, ऐसे नागरिक, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा जिनका नाम वर्तमान में मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या किसी कारणवश पूर्व में मतदाता सूची से नाम विलोपित हो गया है, वे संबंधित मतदान केंद्र पर अपने बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़ावां।

संझा माता के गीत अब सुनाई नहीं देते, संझा थने पूजू सौ-सौ कलिया...

माही की गूंज, बामनिया।

अनंत चतुर्थी के बाद श्राद्ध पक्ष में शुरू होने वाला 16 दिवसीय संझा माता का पर्व शुरू हो चुका है और एक जमाने में घर-घर और गली-गली गूंजने वाले संझा माता के गीत अब बहुत कम सुनाई देते हैं। बामनिया में नारेला रोड, अमरागढ़ रोड, मेला ग्राउंड क्षेत्र में इका-दुका घरों पर संझा माता की स्थापना की गई है। पहले संझा माता की आकृति रोज गोबर और फूलों से बना कर उनकी पूजा की जाती और उनके गीत गाए जाते थे। लेकिन बदलते समय ने गोबर की जगह कागज की प्रिंटिंग वाली संझा ने ले ली है। नारेला रोड पर हिल,रियल, प्रियल गेहलौत द्वारा संझा माता की स्थापना कर संझा के गीत गाए जाते हैं। जिसमें आसपास की लड़कियां भी शामिल होती हैं। गीत सुन के आसपास के लोगों को पुराना समय भी याद आता है जब पूरे मोहल्ले में



संझा के गीतों का अलग ही माहौल होता था। 16 दिन बाद अमावस्या की धूप के बाद नवरात्रि की एकम को संझा माता को नदी के विसर्जित पर उनके घर के लिए बिदाई दी जाती है।

ईमानदारी से नौकरी करना जीवन का लक्ष्य रहा - पुरोहित

माही की गूंज, बामनिया।

पशु चिकित्सालय बामनिया में पोल्ट्री वैक्सीनेटर के पद से 41 वर्षों के गौरवपूर्ण सफर के बाद संतोष पुरोहित ने सेवा निवृत्ति प्राप्त की। इस अवसर पर पशु चिकित्सालय विभाग और परिवारजनों ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पुरोहित की सेवा वर्ष 1985 में रानीखेत बीमारी उन्मूलन योजना (पशु चिकित्सा सेवाएं) झाबुआ से शुरू हुई और वर्ष 1996 से वर्ष 2026 लगातार तीस वर्षों तक बामनिया पशु चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी। सेवाकाल के दौरान पशु चिकित्सा और टीकाकरण का कार्य समर्पित भाव से किया। पशु चिकित्सालय बामनिया परिसर में आयोजन सम्मान समारोह में विभाग झाबुआ, पेटलावद और बामनिया के अधिकारी और डॉक्टर उपस्थित रहे। सेवा निवृत्त चिकित्सक संतोष पुरोहित सम्मान समारोह में भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि, ईमानदारी से नौकरी करना उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। समय से ऑफिस पहुंचना ये मेरी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। पूरे कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की विभागीय शिकायत संतोष पुरोहित के विरुद्ध नहीं होना यही अपने आप में उनकी नौकरी के प्रति लगन को दर्शाता है। सम्मान समारोह के पश्चात पुरोहित अपने परिजनों और मित्रों के साथ डोल के साथ अपने घर पहुंचे और सभी उपस्थितों के प्रति आभार व्यक्त किया।



कथा का दूसरा दिन, मना हनुमान जी का जन्मोत्सव

माही की गूंज, मेहनगर।

गड्ढावदिया धाम के श्रीधर बैरागी महाराज के मुखारविंद से बाफना स्कूल परीसर में तीन दिवसीय चल रही हनुमान कथा के दुसरे दिन बुधवार को श्री हनुमानजी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इनके वर्णन में हनुमान जी की बाल लीलाओं का एवं श्रीराम जी की त्याग एवं गाथाओं का वर्णन किया। इसी कथा के चलते किस प्रकार द्रौपदी चौर हरण को भगवान श्रीकृष्ण ने बचाया, किस प्रकार से द्रौपदी ने श्रीकृष्ण जी को आने पर विवश किया और श्रीकृष्ण जी को द्रौपदी का चौर हरण होने से बचाने क्यों आना पड़ा यह सारा वर्णन कथा में बताया गया। हनुमंत कथा के विश्राम पर चर्चा में श्री गुरुवर ने बताया कि, गड्ढावदिया धाम एवं आसपास में चार गांव लिंवापाड़ा, हवा रुंडी, रूपापाड़ा एवं गड्ढावदिया में पूर्ण रूप से गांव के युवाओं ने श्री बालाजी धाम की प्रेरणा

से शराब मुक्त, नशा मुक्त गांव कर दिया है। जहां कोई भी शराबी ना तो शराब पीकर गांव में आ सकता है और ना ही कोई गांव में शराब बेच सकता है। चारों गांव में पूर्ण रूप से नशाबंदी की गई है। गुरुवर ने बताया कि, यहां पर बालाजी का मंदिर करीब 300 वर्ष पुराना है जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस मंदिर पर पिछले 4 वर्षों से दरबार लगा रहे हैं और यह दरबार मुझे बचपन में करीब 8 वर्ष का था तभी से सब कुछ दिखने लग गया था। जो की धीरे-धीरे मेरी तपस्या और बालाजी महाराज के



आशीर्वाद से 4 वर्ष कथा करते हो गए तथा दिव्य दरबार लगा रहे हैं। इस दरबार में हजारों की संख्या में कैसर एवं लकवा ग्रस्त मरीज आए हैं जिनका 100 प्रतिशत इलाज हुआ है।

सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का होगा पंजीयन

माही की गूंज, झाबुआ।

राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सोयाबीन के न्युनतम समर्थन मूल्य एवं मॉडल वित्तीय दर के अंतर की राशि नियमानुसार उनके बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी।

जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए 46 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) एवं 4 सहकारी विपणन संस्थाओं में पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों का पंजीयन निःशुल्क किया जा रहा है। पंजीयन 3 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो चुका है तथा अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। पंजीयन के पश्चात किसान को पंजीयन क्रमांक प्रदान किया जाएगा।

किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाया गया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों तथा सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन क्रियोपक, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी साइबर कैफे के माध्यम से सशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सशुल्क पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपए प्रति पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

पंजीयन के समय किसान को आधार कार्ड, समग्र आईडी, ऋण पुस्तिका, बैंक खाता पासबुक एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं किसान के आधार तथा अन्य फोटो पहचानपत्रों का परीक्षण कर आवश्यक रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।

सुनहरे कल की आस में 2400 पौधों को वृक्ष बनाने निकले गायत्री परिजन

माही की गूंज, पेटलावद।

अखिल विश्व गायत्री परिवार पेटलावद द्वारा शताब्दी वर्ष के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से संचालित वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत गायत्री उपवन में गत माह आयोजित ऐतिहासिक पौधरोपण में 2400 पौधे रोपे गए थे। इस पुनीत अभियान में नगर एवं क्षेत्र के लगभग 65 सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के सदस्यों ने सहभागिता करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। पौधरोपण को एक माह पूर्ण होने पर गायत्री परिवार द्वारा सभी सहभागी परिजनों से गायत्री

उपवन पहुंचकर अपने हाथों से रोपे गए पौधों का हाल जानने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परिजन उपवन पहुंचे और अपने-अपने पौधों को देखा। पौधों में नई कॉपलें फूटती देखकर परिजनों के चेहरे खिल उठे तथा उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वर्षा की कमी ने बढ़ाई जलसेवा

इस वर्ष अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण नवरोपित पौधों को

नियमित सिंचाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए सेवाभावी परिजनों ने आगे आकर गायत्री उपवन में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के लिए सहयोग का संकल्प लिया। नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही रविवार, 11 अक्टूबर से गायत्री उपवन में पौधों के लिए जलसेवा प्रारंभ की जाएगी। गायत्री परिवार के परिजनों ने कहा कि पौधरोपण केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि पौधों को वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल और संरक्षण की सतत जिम्मेदारी है। एक पौधा लगाना प्रकृति के प्रति संकल्प है, जबकि उसे जीवित रखकर वृक्ष बनाना उस संकल्प की सच्ची

पूर्णता है। गायत्री उपवन में लगाए गए प्रत्येक पौधे को सुरक्षित एवं विकसित करना ही वृक्ष गंगा अभियान की वास्तविक सफलता होगी। इस संरक्षण एवं जलसेवा अभियान में वरिष्ठ गायत्री परिजन मोतीलाल गामड़ सहित जीवन भट्ट, निलेश पालीवाल, राजेन्द्र मोरिया, अनुराग गोड़, सत्यनारायण पालीवाल, डॉ. दुबे, मनीषा दुबे, ललिता भट्ट, वर्धमान जाधव, अजय गेहलौत, प्रकल्प पंवार एवं कन्हैयालाल रामभरोसे का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। गायत्री परिवार ने क्षेत्रवासियों से भी आह्वान किया कि वे इस हरित अभियान से जुड़कर पौधों की सेवा एवं संरक्षण में सहभागी बनें।



चार साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र का मरम्मत कार्य, अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा भवन

गेट पर टूटी टाइल्स, दीवारों में छेद और उखड़ता रंगार, मरम्मत के नाम पर हुई खानापूर्ति



मरम्मत के नाम पर भूखतार की भेट चढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की बदहाली फोटो की मुह्र जुबानी।

माही की गूंज, भामल/खवासा।
सुनील सोलंकी

ग्राम पंचायत परवाड़ा में स्थित उपस्वास्थ्य केंद्र भवन की बदहाल स्थिति अब ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार करीब चार वर्ष पहले भवन का मरम्मत कार्य कराया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद भवन की हालत फिर खराब होने लगी। वर्तमान में भवन की दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं, अंदर कई जगह छेद नजर आ रहे हैं, तथा रंग-रोगन भी उखड़ने लगा है। मुख्य गेट के पास लगी टाइल्स तक टूट चुकी हैं।

भवन की वर्तमान स्थिति देखकर ग्रामीणों का कहना है कि, यदि चार वर्ष पहले ही भवन की

मरम्मत कराई गई थी तो इतने कम समय में भवन दोबारा जर्जर स्थिति में कैसे पहुंच गया...? लोगों ने मरम्मत कार्य की गुणवत्ता और उसमें उपयोग की गई सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं यहाँ वर्तमान में सीएचओ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, सहित 6 कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ थे जिसमें अगर देखा जाए तो यहां सीएचओ एवं एएनएम ही पूरा काम संभाल रहे हैं।

मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति का आरोप

ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि, भवन की मरम्मत के दौरान मात्र खानापूर्ति की गई जिसके चलते मरम्मत के कुछ वर्षों बाद ही भवन की हालत फिर खराब हो गई। दीवारों में दिखाई दे रहे छेद, दरारें, उखड़ता प्लास्टर और खराब होती

टाइल्स देखकर ग्रामीण, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

बदा डामर, हुकली भाभर, शंभु डामर आदि ग्रामीणों का कहना है कि, यदि सरकारी भवनों की मरम्मत में गुणवत्तापूर्ण सामग्री और निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाए तो चार साल के अंदर ही ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पूरे भवन का निरीक्षण करना चाहिए और पूर्व में हुए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की भी जांच करनी चाहिए।

स्वास्थ्य सुविधा देने वाले भवन की हालत ही बदहाल, इलाज केसा होगा?

उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के

लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में जिस भवन में ग्रामीण, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने पहुंचते हैं, उसी भवन की हालत खराब होना अपने आप में गंभीर विषय है। ग्रामीणों का कहना है कि, जब सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन ही सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं है तो ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा किस तरह मिल पाएगी...? यह बड़ा सवाल है।

ग्रामीणों ने बताया कि, भवन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में समस्या और गंभीर हो सकती है।

नए भवन का हो निर्माण

ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की तकनीकी जांच कराकर

वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाए। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि, यदि भवन मरम्मत योग्य नहीं है तो पुराने भवन की बार-बार मरम्मत कराने के बजाय नए सिरे से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

अब देखना यह है कि, चार वर्ष पहले कराए गए मरम्मत कार्य के बावजूद दोबारा खराब हुई भवन की स्थिति पर जिम्मेदार अधिकारी कब संज्ञान लेते हैं और ग्रामीणों की इस मांग पर क्या कार्रवाई की जाती है।

वही मामले को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन झाबुआ स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर रवि भंवर से माही की गूंज ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।

वही मामले को लेकर माही की गूंज ने उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यभार देख रहे थांदला

सिविल अस्पताल के अधीन ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जॉन खराड़ी से चर्चा की तो उनका कहना था कि, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, यह भवन पुराना है, अभी इसकी मेंटेनेंस की राशि भी नहीं आ रही है, बाकी तो जो है वैसा चल रहा है। उनका कहना था कि, उप स्वास्थ्य केंद्र पर अभी कई प्रकार की दवाइयां ग्रामीणों को मिल रही हैं अगर वहां कोई समस्या है, तो मैं मामले को देखता हूं।

उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ सीएचओ हेमलता संगीतरा से चर्चा की तो उनका कहना था कि, मुझे यहां आए साल भर हुआ है, इससे पहले से ही यहां के भवन की हालत खराब है फिर भी हम कार्य कर रहे हैं। अभी आशा कार्यकर्ता सहित हम 6 कर्मचारी कार्य देख रहे हैं, यहां जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनको खवासा अटेंच कर रखा है।

एक शाम अणु के नाम का हुआ आयोजन

माही की गूंज, थांदला।

जिन शासन गौरव के आत्माथी

पंडित रत्न जैनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनिजी म.सा.के उपकारों को याद करने पूज्य श्री धर्मदास सम्प्रदाय में गुरु पखवाड़ा चल रहा है। जिसके अंतर्गत जंगम युग प्रधान जैनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री धर्मदासजी म.सा. से लेकर उनकी वर्तमान शिष्य सम्प्रदाओं में प्रवर्तक पद को दीपा रहे बुद्धपुत्र पूज्य श्री जिनेन्द्रमुनिजी म.सा. तक के सभी गुरुभगवतों को याद करते हुए उनके गुणगान किये जा रहे हैं। थांदला में तत्त्वज्ञ पूज्य धर्मेन्द्र मुनिजी व रोचक वक्ता पूज्य सन्दीप मुनिजी तथा महासती पूज्या निखिल शीलजी आदि ठाणा-12 के पावन सानिध्य में चल रहे धर्मोत्कर्ष वर्षावास में त्रिदिवसीय अणु स्मृति दिवस का भव्य आयोजन हुआ। जिसके अंतर्गत प्रातः 9 बजे गुरु गुणानुवाद सभा का

आयोजन हुआ जिसमें पूज्य गुरुभगवतों ने उमेश मुनिजी म.सा. को महान साधक तथा उनकी क्रिया



को ही उपदेश बताते हुए उनके वचनानुसार को आगम वाणी कहा। आपके ही पावन सानिध्य में थांदला श्रीसंघ द्वारा दोपहर 2 से 3 बजे तक वैकल्पिक प्रश्नमंच का आयोजन हुआ। जिसमें 11 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के श्रावक-श्राविकाओं ने हिस्सा लेकर गुरुभक्ति पर आधारित प्रश्नोत्तरी के सही विकल्प चयन कर उस पर मुहर लगाई।

पूज्य भूमि थांदला में जैनाचार्य

द्वय पूज्य जवाहरलालजी व पूज्य श्री उमेश मुनिजी अणु ने तो जन्म लिया ही है वहीं उनकी ही विरासत को आगे बढ़ाने वालें संतों में यहाँ विराजित 8 संतों में पूज्य तत्त्वज्ञ धर्मेन्द्र मुनिजी, सन्दीप मुनिजी, प्रशस्त मुनिजी व सुव्यस मुनिजी ये चार संत भी थांदला के नन्दन हैं। इनमें वर्तमान के अणुभक्त गुरुदेव की छवि देखते हैं। ऐसे में सायं प्रतिक्रमण के बाद आयोजित एक शाम अणु के नाम में श्रावकवर्ग का पौषध भवन पर व श्राविकाओं का महिला स्थानक पर अपार उत्साह देखने को मिला। गुरुभगवतों के साथ उपस्थित अणु भक्तों ने एक से बढ़कर एक गीत, भजन, स्तवन आदि सुनाते हुए थांदला के नन्दन कोटि-कोटि वंदन के जयकारों से पूरा स्थानक अणु वचनों के शुभ पुद्गलों से भर दिया। अणु भजनानुसार में आये अणु भक्तों को धर्मोत्कर्ष परिवार द्वारा प्रभावना भी प्रदान की गई।

क्षेत्र में स्टापडेम पर कड़ी-शटर लगवाने के निर्देश

माही की गूंज, पेटलावद।

वर्षा ऋतु की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव जैन ने क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी के विशेष निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

जारी आदेश के अनुसार, सभी ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में स्थित स्टापडेम पर तत्काल कड़ी-शटर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। शटर लगवाने के पश्चात इसके फोटो अनुभाग पेटलावद को भेजना अनिवार्य होगा तथा इसका प्रमाण-पत्र जनपद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कहीं कड़ी-शटर उपलब्ध न हो, तो जन सहयोग के माध्यम से बोरी बंधन करवाकर पानी रोकने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए इस कार्य को अत्यंत प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने बताया, वर्षा ऋतु समाप्त होने के तुरंत बाद जल संरक्षण के लिए हर स्टापडेम पर कड़ी-शटर लगाना या बोरी बंधन करना अनिवार्य है। जल संचय के इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं करे। जन सहयोग लेकर पानी की एक-एक बूंद को सहेजें।

उत्कृष्ट एनसीसी कैडेट्स का सम्मान



माही की गूंज, थांदला

सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत लायंस क्लब थांदला द्वारा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित सेवा सप्ताह के पंचम दिवस स्थानीय सांदीपनि विद्यालय परिसर में एनसीसी की मूल भावना +एकता और अनुशासन+ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में क्षेत्र के तहसीलदार सुकदेव डावर, झोन चेरमैन लायन जीवन भंडारी, डिस्ट्रिक्ट चेरपरसन लायन नवीन बैरागी, सांदीपनि विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सरिता

ओझा, लायंस क्लब अध्यक्ष ओमप्रकाश बजाज, पूर्व अध्यक्ष किशोर पंडित (नानु सेठ), पूर्व अध्यक्ष चिराग घोड़ावत, सचिव लायन दिनकर बाजपेई, सेवा सप्ताह संयोजक सुधीर शर्मा एवं एनसीसी अधिकारी गौरव चौहान सहित अतिथिगण उपस्थित रहे।

राष्ट्र सेवा का संदेश
एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए तहसीलदार सुकदेव डावर ने कहा कि, एनसीसी की मूल भावना +एकता और अनुशासन+ पर आधारित है। कैडेट्स ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर

राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपदा अथवा आपात स्थिति में एनसीसी कैडेट्स सेवा के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में तैयार रहते हैं। झोन चेरमैन लायन जीवन भंडारी ने कहा कि, +सेवा परमो धर्म+ और +एकता एवं अनुशासन+ के मूल मंत्र को जीवन में उतारने का समय है। लायंस क्लब अध्यक्ष ओमप्रकाश बजाज ने कहा कि, कैडेट्स की ऊर्जा अभियान की ताकत है और उनका अनुशासन समाज के लिए मिसाल है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एनसीसी कैडेट्स को अतिथियों द्वारा +बेस्ट सेवा कैडेट+ के प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सरिता ओझा, झोन चेरमैन जीवन भंडारी एवं एनसीसी अधिकारी गौरव चौहान को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को फल, फूट वितरित किए गए।

मैदान में होंगे किसान: नर्मदा का पानी माही में लाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने की योजना



सिंचाई के लिए पानी देने के बाद जो स्थिति बनती थी आज बनी हुई है।

माही की गूंज, पेटलावद।

अल्प वर्षा के चलते पानी की भारी किल्लत भविष्य में होना है और किसानों के सामने अगली फसल को बोने और कपास की फसल को बचाने तक की चुनौती है। जिससे निपटने के लिए किसानों ने सरकार से मांग की है कि नर्मदा का पानी जो धार जिले तक पहुंचा है उसे माही डेम में छोड़ा जाए जिससे डेम का वाटर लेवल बढ़े और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाए। फिलहाल कम वर्षा के चलते डेम में सिर्फ पीने के पानी की उपलब्धता है और प्रशासन ने कई स्थानों पर पीने के पानी के स्टॉक को बनाए रखने के लिए सिंचाई के लिए पानी उपयोग करने पर रोक लगा दी है। भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिनों पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंप कर इस मांग को रख चुके हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय और जिला प्रशासन ने आने वाले समय में जल संकट को देखते हुए किसानों की मांग को जायज मानते हुए अपनी ओर से पत्र व्यवहार संबंधित विभाग की ओर कर दिया है। जिसके

बाद उम्मीद थी कि, नर्मदा का पानी माही डेम में छोड़ दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिससे किसानों में भारी आक्रोश है और अब किसान आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं।

आज से भूख हड़ताल और धरना

भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र पाटीदार और महेंद्र हामड ने बताया कि, गुरुवार को क्षेत्र भर के किसान पानी की समस्या के स्थानीय निराकरण नहीं होने तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। किसान संघ के नेतृत्व में मंडी परिसर पेटलावद में धरना और भूख हड़ताल शुरू होगी।

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड ने बताया कि, हमारी प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है और उनकी ओर से भी इस क्षेत्र में हर संभव प्रयास जारी है, अगर समय रहते इसका निराकरण होता है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। दूसरी ओर धार जिले में भी किसान इस मुद्दे को लेकर आक्रोशीत हैं और एक-दो दिन बाद वहां भी किसान संघ जल सत्याग्रह करने की चेतावनी

दे चुका है।

भारी जल संकट आ सकता है

प्रशासन खुद इस बात को मान रहा है कि, आने वाले समय में जल संकट ऐसा ही बना रहा तो ये बड़ी चुनौती बन कर सामने आ सकता है। माही डेम वर्तमान में उतना ही भरा हुआ है जहां से सिर्फ पीने के पानी की पूर्ति कर सकता है वो भी समय के साथ-साथ मुश्किल चुनौती बनना तय है। अगर नर्मदा का पानी माही तक पहुंच जाता है तो काफी कुछ समस्या कम हो सकती है। ज्ञात है कि बारिश की कमी के चलते वर्तमान में नदी, तालाब और जल के दूसरे स्रोत में पानी कम है और कई स्थान पर नलकूप तक कम वर्षा के चलते रिचार्ज भी नहीं हो पाए हैं। गुरुवार से शुरू होने वाले किसान आंदोलन पर अब सब की नजरे टिकी है। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि, इस आंदोलन में हर आदमी को जुड़ना चाहिए क्योंकि समस्या केवल किसान की ही नहीं। अगर पानी माही डेम में नहीं आया तो कई गांवों में बड़ा जल संकट पीने के पानी का खड़ा होना तय है और खेती किसानों पर क्षेत्र का पूरा व्यापार व्यवसाय टिका हुआ है।



माही डेम में इस बार जल स्तर काफी गिरा हुआ है।

संपादकीय

रोशनी से न्यूरोसाइंस को समझने में मिली मदद

मानवता के कल्याण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिस प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, इस बार चिकित्सा विज्ञान में खोज के लिये दिया जा रहा पुरस्कार उस कसौटी पर खरा उतरता है। मेडिसिन के लिये वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका और जर्मनी के तीन वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। कार्ल डेसरथ, पीटर हेगमान और जॉर्ज नेगल को यह सम्मान दिमाग की कोशिकाओं को रोशनी से नियंत्रित करने वाली खोज के लिये मिला है। इस खोज ने दिमाग के अध्ययन करने का एक नया तरीका वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया है। उनकी खोज व अनुसंधान से 'ऑप्टोजेनेटिक्स' तकनीक विकसित करने में मदद मिली है, जो मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिये रोशनी का प्रयोग करती है। दरअसल, इस तकनीक का विचार इसके जटिल नाम से ज्यादा आसान है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के मस्तिष्क में अरबों नर्व सेल्स यानी न्यूरोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिये आपस में संवाद स्थापित करते हैं। विज्ञानी लगातार खोज करते रहे हैं कि मस्तिष्क की सक्रियता, याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने में न्यूरोन्स समूहों की कैसी भूमिका होती है। निस्संदेह, यह वैज्ञानिकों के लिये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि आधुनिक तकनीकों से दिमाग की गतिविधि पर तो नजर रखी जा सकती थी, लेकिन विभिन्न कोशिकाओं को ठीक से नियंत्रित करना कठिन था। इस खोज की शुरुआत पीटर हेगमान द्वारा हरे शैवाल के रोशनी की ओर तैरने के रहस्य को सुलझाने से हुई। हेगमान और नेगल ने एक ऐसा प्रोटीन खोजा जो नीली रोशनी पड़ने पर आयन चैनल खोलकर इलेक्ट्रिकल हलचल पैदा करता है। वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया कि यह प्रोटीन रोशनी पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। अंततः इस खोज का प्रयोग न्यूरोन्स को रोशनी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये किया गया। इसके बाद ही शोधकर्ता दुनिया तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या निष्क्रिय करके देख सके कि इसका कैसा प्रभाव होता है।



एस.एस.कुंशी

क ई महीनों से, मतदाता सूची में 'विशेष ग ह न पुनरीक्षण' य 1 न 1 एसआईआर ने मतदाताओं को परीक्षा में डाल रखा है। सोमवार को, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्रीय चुनाव आयोग के फ़ैसले लेने के तौर-तरीके पर सवाल उठे।

न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जो इन खबरों से जुड़ी थीं कि चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के नाम पर लिए गए, फ़ैसलों या कामों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां जताई थीं। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की मांग की। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करके सही किया कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर और एकतरफ़ा तौर पर ऐसा असाधारण कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि आयोग के फ़ैसले आम सहमति से हों; जहां आम सहमति संभव न हो, वहां निर्णय बहुमत के आधार पर हो। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अगर रिकॉर्ड से पता चलेगा कि कुछ निर्णय विशेष इस नियम के उलट लिए गए थे तो अदालत उन पर रोक लगा सकती है, उन्हें अधिकार-क्षेत्र से बाहर धोषित कर सकती है।

अब एक नोटिस जारी किया गया है- विस्मयित साबित करने में संबंधित लोगों का पक्ष सुना जाएगा। लेकिन विवाद का स्वरूप पूरी तरह बतल गया है। अब सवाल सिर्फ़ यह नहीं रहा कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशासनिक रूप से सुस्पष्ट है। इससे भी पहले एक सवाल उठता है - क्या कुछ विवादित

काम कानूनी तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के फ़ैसले थे भी या नहीं?

2023 के कानून की धारा 18 स्पष्ट है। इसका मुख्य कामकाज आम सहमति से होना चाहिए; जहां पर आयुक्तों की राय अलग-अलग हों, तो फ़ैसला बहुमत के आधार पर लिया जाए। यह सिद्धांत 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों' से भी पुराना है (संदर्भ -नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम)। मुख्य चुनाव आयुक्त एक अध्यक्ष हैं, न कि एक कमांडर। सर्वोच्च न्यायालय ने टीएन शेषन मामले में भी यही कहा था। तीन सदस्यों वाली संवैधानिक संस्था में, दो सदस्यों की एक जैसी राय ही बहुमत है। किसी सामूहिक संस्था के भीतर मतभेद होना सामान्य है, यहां तक कि जब सब 'ठीक' हों। जो चीज मायने रखती है, वह यह कि बाद में क्या होता है। अगर आयुक्त 'अ' कोई एक प्रस्ताव रखता है और बाकी दो 'भिन्न राय' दर्ज करते हैं, तो 'अ' के प्रस्ताव को 'केंद्रीय चुनाव आयोग' का फ़ैसला नहीं कहा जा सकता।

फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत एक कानूनी प्रपत्र है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के हवाले से आई रिपोर्ट से पता चला कि आयुक्त जोशी ने मई में एक प्रशासनिक निर्देश के जरिए एसआईआर की जरूरतों में अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। यह कहकर कि कानूनी फॉर्म में बदलाव के लिए पहले नियमों में संशोधन की जरूरत है। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू भी इससे सहमत थे। फिर भी, बदली हुई ऑनलाइन प्रक्रिया इसीआई नेट



पर दिखाई दी। सोमवार को मामला नए मोड़ पर पहुंचा, जब फॉर्म 6 में बदलाव का मुद्दा उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने साफ़ किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अनुमोदन नहीं किया था। यह भी कि अदालत इस बात की जांच करेगी कि 'किसने क्या बदलाव किया है'। अब यही सवाल केंद्र में हो गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 'फॉर्म 6' ने एक और दिलचस्प भूमिका ले ली है। आयोग ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कि वे पुरानी और संशोधित वोटर लिस्ट की तुलना करें। फिर उन पात्र मतदाताओं की पहचान की जाए, जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्हें फिर से शामिल करने में मदद करें। यह सुधारात्मक कदम बहुत अच्छा है। लेकिन जिस मतदाता का नाम 10, 20 या 30 साल से वोटर लिस्ट में था और एसआईआर के दौरान हटाया गया, उसे 'नए' मतदाताओं के लिए बने फॉर्म का इस्तेमाल करने और यह झूठा बयान देने के लिए क्यों और कैसे कहा जा सकता है कि वह पहली बार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है-नियमों के अनुसार ऐसा आपराधिक कृत्य है, जिसमें एक साल तक जेल की सजा हो सकती है?

सूची से हटाया गया मतदाता नया मतदाता नहीं होता। उसे लिस्ट में वापस शामिल किए जाने की जरूरत है, न कि पहली बार पंजीकरण की। अगर मौजूदा फॉर्म इसके लिए सही नहीं हैं, तो नियमों में बदलाव करके एक नया फॉर्म बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल का मामला बड़ा संस्थागत सवाल खड़ा करता है।

जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के जरिए 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद, खबरों के अनुसार 22.21 लाख लोगों ने नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की गयी है। इसके अलावा, 16.10 लाख अपीलें वे मिलीं, जिनमें उन नामों को चुनौती दी गई, जो मतदाता सूची में शामिल किए गए। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू ने फाइल पर पृष्ठ था कि 'केंद्रीय चुनाव आयोग' की ओर से यह अपीलें दायर करने के लिए कौन अधिकृत था? सवाल का पूरा जवाब मिलना चाहिए।

गोवा का मामला भी ऐसा ही है, जहां मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारियों ने 97 मतदाताओं को लिस्ट में वापस शामिल किए जाने के योग्य पाया, लेकिन केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित सॉफ्टवेयर ने ऑटम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले उन्हें वापस शामिल करने की इजाजत नहीं दी। सॉफ्टवेयर कानूनी अधिकारियों के फैसलों से ऊपर नहीं हो सकता। इसीआई नेट एक समानांतर चुनाव अधिकार संस्था नहीं बन सकता।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 26 सितंबर की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के जरिए 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद, खबरों के अनुसार 22.21 लाख लोगों ने नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की गयी है। इसके अलावा, 16.10 लाख अपीलें वे मिलीं, जिनमें उन नामों को चुनौती दी गई, जो मतदाता सूची में शामिल किए गए। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू ने फाइल पर पृष्ठ था कि 'केंद्रीय चुनाव आयोग' की ओर से यह अपीलें दायर करने के लिए कौन अधिकृत था? सवाल का पूरा जवाब मिलना चाहिए।

की संस्थागत स्तर पर जांच होगी, चुनाव आयुक्तों के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसीआई नेट को चुनावी कानूनों के अनुरूप बनाने पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन हर सुधार अतीत के बारे में एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे सुधार उपाय पहले से स्वचालित क्यों नहीं थे?

केंद्रीय चुनाव आयोग का यह कहना है कि उसके फ़ैसले सर्वसम्पत्ति से लिए गए थे और राय में भिन्नता भी चर्चा का एक अंग होती है। इसीलिए अपनी इस बचाव मुद्रा को अब रिकॉर्ड से साबित करें। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर पहले से कोई राय नहीं बनाई है। यानी फाइलों को सच बताने दें। भारत को एक पारदर्शी संस्थागत बही-खाते की जरूरत है - आयोग के सामने क्या प्रस्ताव रखे गए, उसे किसने मंजूरी दी, किसने असहमति जताई, अंत में क्या फ़ैसला हुआ और किसके अधिकार से उसे लागू किया गया।

निःसंदेह, केंद्रीय चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संवैधानिक आज़ादी का मतलब कानून से आज़ादी नहीं है। वह संस्था जो चुनावी कानूनों का पालन करने की मांग करती हो, उसे खुद भी मिसाल पेश करने वाला आचरण दिखाना चाहिए। निःसंदेह, चुनाव आयोग व्यक्ति न होकर एक संस्था है। इसकी विश्वसनीयता दशकों में उन आयुक्तों, अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओं ने बनाई है, जिन्हें भरोसा था कि अपंगार अपने ही नियमों का पालन करते हैं।

निःसंदेह, एक बात पर किसी फ़ैसले की जरूरत नहीं है-संसद ने तीन सदस्यों वाला आयोग बनाया है और यह तय किया है कि असहमति होने पर फ़ैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। वहां एक व्यक्ति खुद अपने आराम में संस्था की जाह्न नहीं ले सकता। जब कोई कार्यवाई मतदाता और चुनाव आयोग के नाम पर की जाए, तो लोकतंत्र एक सरल सवाल पूछने का हकदार है - फ़ैसला किसका था?

शिक्षा क्रांति का अधूरा सच और जमीनी हकीकत

देश में आम आदमी के 'अच्छे दिन' का वादा लंबे समय से किया जा रहा है। इसे साकार करने के लिए शिक्षा और चिकित्सा जैसे जनकल्याणकारी मॉडल सामने रखे गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिकों से लेकर आयुष्मान भारत तक, गरीब और आम नागरिक को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बावजूद इसके, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की अधूरी सुविधाओं के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग महंगे निजी अस्पतालों का रुख करने को विवश हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति और नवजागरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इन संकल्पों का वास्तविक लाभ आम आदमी तक प्रभावी रूप से पहुंचना अभी एक बड़ी चुनौती है।

प्रशासन का दावा है कि डिजिटल तकनीक और कृत्रिम मेधा से लेकर अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, कृषि, मौसम और उत्पादकता संबंधी शोध तक भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इसी उपलब्धि के आधार पर नई शिक्षा नीति को रोजगारपरक और व्यापक शिक्षा क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन हो चुका है और

अधिकांश विद्यालय बुनियादी भवन एवं स्वच्छता सुविधाओं से लैस हैं। ऐसे दावों के बीच यह उम्मीद जताई जाती है कि निकट भविष्य में चिकित्सा और शिक्षा-दोनों क्षेत्रों में भारत स्वयं एक अनुकरणीय मॉडल बन जाएगा। हालांकि इन उपलब्धियों और दावों का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि इनका लाभ देश की विशाल आबादी के अंतिम व्यक्ति तक कितनी प्रभावी और समान रूप से पहुंच रहा है।

लेकिन जब स्कूली और उच्च शिक्षा की वास्तविक स्थिति की पड़ताल करते हैं, तो तस्वीर सरकारी दावों से कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। उच्च शिक्षा के बढ़ते निजीकरण ने शिक्षा को सुलभ और छात्र-केंद्रित बनाने के बजाय उसे तेजी से औपचारिक शिक्षा नीति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन हो चुका है और



नकल जैसी समस्याएं इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। विडंबना यह है कि शिक्षा क्रांति के नाम पर ज्ञान और शोध से पहले कारोबार का विस्तार दिखाई देने लगा है। सरकार द्वारा शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक निवेश न किए जाने और निजी क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता ने इस प्रवृत्ति को और मजबूत किया है। जहां शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक विकास और ज्ञान-सृजन होना चाहिए, वहां लाभ और राजनीतिक हित हावी होने लगते हैं। परिणामतः विश्वविद्यालयों के विशाल परिसर और बढ़ती छात्र संख्या के बावजूद शोध, पाठ्यक्रम और शिक्षण की

गुणवत्ता में अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता।

शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें छात्र पढ़ाई के साथ काम करने की सुविधा और प्रेरणा भी पा सकें, लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी भी परीक्षा, दृश्यन और अंकों की प्रतिस्पर्धा तक सीमित दिखाई देते हैं। सरकार ने शिक्षा और काम को साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। शिक्षा

क्रांति के तहत बेहतर इमारतों, शौचालयों और पेयजल जैसी सुविधाओं के दावे तो किए गए हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा जारी रखने की वास्तविक चुनौती अब भी बनी हुई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट इन दावों से अलग तस्वीर सामने रखती है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की रफ्तार धीमी है। आज भी करीब 1.2 करोड़ बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और लगभग पांच करोड़ स्कूली बच्चे स्वच्छता, शौचालय और वाशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

शिक्षा के ढांचे को डिजिटल और कृत्रिम

मेधा के अनुरूप बदलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चंद शहरी स्कूलों को छोड़ कर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है। उनके लिए कोई समानांतर और सुनिश्चित शिक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती; कुछ लोगों द्वारा चलाए जा रहे अधूरे प्रयासों के अलावा व्यापक स्तर पर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। जबकि उन्हें भी शिक्षा का पूरा अधिकार है और हर शहर में स्कूली स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसीलिए शिक्षा क्रांति के दावों और उसकी वास्तविक तस्वीर के बीच अंतर दिखाई देता है। इन दावों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा क्रांति के अधूरे पक्षों को भी पूरा करना होगा।



सुरेश सेठ

पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का अवसर

श्राद्ध और तर्पण को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, स्मृति, कृतज्ञता और पीढ़ियों से मिले संस्कारों को समझने की एक भारतीय दृष्टि के रूप में भी देखा जा सकता है। हमारे जेहन में शायद अपने पूर्वजों के नाम, गांव, कुछ पारिवारिक घटनाओं और उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां ही हैं। लेकिन हमारी सोच, व्यवहार, डर, आदतें और जीने के कुछ तरीके भी पिछली पीढ़ियों से हम तक पहुंचे हो सकते हैं।



गणेश काला

विज्ञान के मुताबिक, हमारी जैविक संरचना में डीएनए की अहम भूमिका है। हमें अपने माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री मिलती है और इस तरह जैविक निरंतरता पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है। वहीं शोधों में सामने आया कि जीन की अभिव्यक्ति पर माहौल, जीवनशैली और अनुभवों का प्रभाव पड़ सकता है। इसे समझने को एपिजेनेटिक्स अहम क्षेत्र है। यहीं से भारतीय परंपरा में पूर्वजों के स्मरण व श्राद्ध-तर्पण को देखने का नया रास्ता खुलता है।

मानव शरीर का बड़ा हिस्सा जल से बना है। भारतीय दर्शन ने जल को पंचमहाभूतों में स्थान दिया। वहीं तर्पण में जल अर्पित करने में गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है- 'मैं अपने अस्तित्व की उस धारा को स्वीकार करता हूँ, जो मुझसे पहले भी थी और मेरे बाद भी आगे जाएगी।' जल अर्पित करते समय व्यक्ति पूर्वजों का नाम लेता है। अपने अतीत को याद

कर स्वीकार करता है कि उसका वर्तमान अकेले उसने नहीं बनाया।

यह प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। कई भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते। किसी पूर्वज के प्रति कृतज्ञता, पुराने पारिवारिक दुख की याद या पीढ़ियों से चली आ रही अनकही कहानी-इन सबका हमारे मन पर प्रभाव हो सकता है। श्राद्ध व्यक्ति को उन भावनाओं को देखने और स्वीकार करने का अवसर देता है। हम केवल अपना वर्तमान लेकर पैदा नहीं होते। हमारा व्यक्तित्व परिवार, समाज, संस्कार, वातावरण और अनुभवों से बनता है। परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही कुछ आदतें और व्यवहार भी अगली पीढ़ियों में दिख सकते हैं। लेकिन इसे सीधे यह कहना कि 'पूर्वजों की स्मृतियां डीएनए में रिकॉर्ड होकर उसी रूप में हमारे भीतर चलती हैं', वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। डीएनए और व्यवहार के बीच संबंध कहीं अधिक जटिल है।

आनुवंशिकता, वातावरण और जीन-अभिव्यक्ति के अध्ययन ने यह समझने का रास्ता जरूर खोला है कि जीवन के अनुभव जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक पीढ़ियों के बीच जैविक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से 'पूर्वजों के डीएनए



पैटर्न की हीलिंग' को वैज्ञानिक सिद्ध तथ्य के बजाय एक विचारवादी रूपक के रूप में समझना अधिक उचित होगा।

जल और भावनाओं के संबंध की चर्चा में जापानी लेखक और शोधकर्ता मसारा इमोटो का नाम अक्सर लिया जाता है। हालांकि उनके निष्कर्षों को मुख्यधारा के वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर भी भारतीय तर्पण परंपरा को समझने में जल का प्रतीकात्मक महत्व इससे कहीं पुराना है। भारतीय चिंतन में जल केवल भौतिक पदार्थ नहीं, जीवन और चेतना की यात्रा का प्रतीक भी रहा है।



अस्तित्व मूलतः विभाजित नहीं है। व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, लेकिन व्यापक अस्तित्व में सब एक ही निरंतरता का हिस्सा हैं। आधुनिक विज्ञान की भाषा अलग है। विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा, कोशिका, अणु, परमाणु, आनुवंशिकी और जैविक प्रक्रियाओं की बात करता है। फिर भी दोनों के बीच एक संवाद संभव है। ब्रह्मांड में पदार्थ निरंतर रूप बदलता है। पृथ्वी के तत्व हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं। भोजन शरीर में जाता है। शरीर प्रकृति में लौटता है। जीवन की जैविक निरंतरता पीढ़ियों के जरिए आगे बढ़ती है। भारतीय चिंतन इसी

इसलिए तर्पण के समय जल अर्पित करने को ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया मान सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अतीत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है व अपना वर्तमान उस परंपरा से जोड़ता है। श्राद्ध का सबसे बड़ा परिवर्तन शायद हमारे भीतर होता है। जब कोई श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, तो वह स्वयं अपने जीवन को देखने लगता है कि जीवन केवल 'मैं' तक सीमित नहीं है। मेरे भीतर मेरे माता-पिता हैं। मेरे माता-पिता के भीतर उनके माता-पिता की जीवन-कथा है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं को एक लंबी जीवन-श्रृंखला की कड़ी के रूप में देख सकता है। यहीं श्राद्ध कृतज्ञता की परंपरा बन जाता है।

अद्वैत दर्शन भी कहता है कि अस्तित्व मूलतः विभाजित नहीं है। व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, लेकिन व्यापक अस्तित्व में सब एक ही निरंतरता का हिस्सा हैं। आधुनिक विज्ञान की भाषा अलग है। विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा, कोशिका, अणु, परमाणु, आनुवंशिकी और जैविक प्रक्रियाओं की बात करता है। फिर भी दोनों के बीच एक संवाद संभव है। ब्रह्मांड में पदार्थ निरंतर रूप बदलता है। पृथ्वी के तत्व हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं। भोजन शरीर में जाता है। शरीर प्रकृति में लौटता है। जीवन की जैविक निरंतरता पीढ़ियों के जरिए आगे बढ़ती है। भारतीय चिंतन इसी

निरंतरता को पंचमहाभूत, जीवन-चक्र और पूर्वज परंपरा की भाषा में देखता रहता है।

वैज्ञानिक प्रमाण यह नहीं कहते कि श्राद्ध या तर्पण करने से किसी का डीएनए सीधे बदल जाता है। इसी तरह तर्पण को आनुवंशिक रोगों के उपचार का वैज्ञानिक तरीका भी नहीं माना जा सकता। लेकिन मनुष्य केवल डीएनए नहीं। उसके भीतर स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं, रिस्ते, संस्कार हैं और जीवन को देखने की धारणाएं हैं। यदि किसी पारिवारिक दुख को समझने, स्वीकारने व उसके साथ स्वस्थ संबंध बनाने से व्यक्ति के तनाव और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है, तो उसका प्रभाव मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। इस तरह 'हीलिंग' का अर्थ डीएनए बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक व व्यावहारिक धारणाएं पहचानना हो सकता है।

आजकल बच्चों को अपने दादा-दादी और परदादा-परदादी की कहानियां तक पता नहीं होतीं। ऐसे समय में श्राद्ध हमें पूछने का अवसर देता है-हम कहां से आए हैं और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? शायद तर्पण केवल अतीत को जल देने का नाम नहीं है। खुद में कृतज्ञता जगाने का अवसर भी है। यह भी कि हम एक लंबी जीवन-यात्रा की कड़ी हैं।

शायद यही श्राद्ध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है-पूर्वजों को मुक्त करने से पहले अपने भीतर जमा भावनाओं को मुक्त करना। जब श्रद्धा भय से निकलकर कृतज्ञता बनती है, तब श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं रहता। वह आत्मचिंतन बन जाता है, परिवार की स्मृति बन जाता है। ...और आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण बन जाता है।

74 गोशालाएं बनने के बाद भी सड़कों पर 10 हजार गोवंश

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले की सड़कों पर निराश्रित गोवंशों की संख्या कम नहीं हो रही है, जबकि जिले में शासन द्वारा 74 नई गोशालाओं का निर्माण किया और संचालन भी शुरू कर दिया है। इसके बावजूद अभी भी 10 हजार से अधिक गोवंशी सड़कों पर ही आसरे की तलाश में घूम रहे हैं। इसके कारण कई बार हादसे हो रहे हैं, गोवंश भी घायल हो रहे हैं। सीतामऊ के समीप मोरखेड़ा में प्रस्तावित गो-अभयारण्य निर्माण के लिए भी अभी प्रक्रिया की गति बढ़ी नहीं है।

जिले में सड़कों पर घूमने वाले गोवंशी के लिए सरकार ने गोशालाएं खोली हैं। इनके निर्माण में करोड़ों रुपये भी खर्च किए गए हैं। गोशालाओं में गोपालन शुरू हो गया। बावजूद अभी भी हजारों गोवंशी सड़कों पर घूम रहे हैं। निराश्रित गोवंशी किसानों और आमजन के परेशानी का कारण बने हुए हैं। ये खेतों में फसलों को बर्बाद करते हैं तो शहरी क्षेत्र में भी यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं में परेशानी होती है। कई बार गोवंशी भी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।

74 गोशालाओं में गोपालन शुरू

जिलेभर में कुल सात लाख मवेशी हैं। इनमें से 10 हजार से अधिक निराश्रित गोवंशी हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं। निराश्रित गोवंशी को सहारा देने के लिए राज्य शासन द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर ग्राम पंचायतों में गोशालाएं बनाई जा रही हैं। दो चरणों में जिले में 74 गोशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनमें से 72 में

गोपालन चल रहा है। ग्राम तलाब पिपलिया व रणायरा गोशाला की अभी पंजीकरण की कार्रवाई चल रही है, जल्द ही इन दोनों गोशालाओं का भी संचालन प्रारंभ हो जाएगा।

74 गोशालाएं बनने के बाद भी सड़कों पर निराश्रित गोवंशी की झुंड कम नहीं हो रहे हैं। जिला मुख्यालय की सड़कों पर बड़ी संख्या में गोवंशी मुख्य मार्गों की सड़कों, मोहल्लों, कालोनियों में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं गांवों में घूमने वाली निराश्रित गोवंशी किसानों की फसलों को चौपट करती हैं। जिससे किसान भी परेशान रहते हैं। कई बार गोवंशी दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। मुख्य मार्गों से लेकर कालोनियों की सड़क पर विचरण कर रहा गोवंशी आमजन के लिए भी मुसीबत बना हुआ हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब दो गोवंशी सड़क पर लड़ते हैं। सड़क पर गोवंशी के विचरण से सब्जी मंडी, सम्राट मार्केट, सदर बाजार, नई आबादी सहित शहर के सभी क्षेत्रों में परेशानी हो रही है।

एक गोशाला निर्माण पर खर्च हुआ 27.71

लाख रुपये

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर पंचायत में गोशाला खोलने का वादा किया था, सत्ता में आते ही सरकार ने इस वादे को निभाया। कांग्रेस के शासन में मंदसौर जिले में पहले चरण में 36 गोशालाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन गोशालाओं का निर्माण जारी रहा। दूसरे चरण में राज्य शासन ने जिले की पंचायतों में 38 गोशालाएं बनाने का



कार्य शुरू किया। अब तक दोनों चरणों की सभी 74 गोशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक गोशाला में 27.71 लाख की लागत से आवश्यक कार्य हुए हैं। इनमें चरगाहा भी शामिल है।

जिले की गोशालाओं में 16 हजार गोवंशी का हो रहा पालन

जिले की 23 गोशालाओं में 8500 गोवंशी और नवीन 72 गोशालाओं में करीब साढ़े सात हजार गोवंशी का पालन हो रहा है। पशुपालन विभाग के अनुसार गरोट

व बानपुरा क्षेत्र में अधिक संख्या में निराश्रित पशु हैं। एक साल पहले हुए सर्वे के अनुसार जिले में सभी प्रकार के पशुओं की संख्या करीब सात लाख है। अकेले मंदसौर शहर में सड़कों पर करीब एक हजार से अधिक गोवंशी सड़कों पर घूमते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निराश्रित पशु खेतों में नुकसान करते हैं।

जिले में मनरेगा के तहत 74 गोशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। दोनों चरणों में तैयार हुई गोशालाओं में से 72 में गोपालन शुरू हो गया है। दो गोशालाओं का संचालन भी जल्द शुरू होगा। - प्रदीप चौहान, मनरेगा अधिकारी, मंदसौर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आई दरार

माही की गूंज, रतलाम।

करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत से बने दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रतलाम से गुजर रहे एक्सप्रेस-वे की नई दिल्ली जाने वाली लेन पर शिवगढ़ के पास अंडरपास के ठीक ऊपर दरार दिखाई दी है। सूचना मिलने के बाद एनएचआई ने ट्रैफिक डायवर्ट कर प्रभावित हिस्से में सुधार कार्य शुरू करा दिया है।

अंडरपास के ऊपर ब्रिज डेक स्लैब में मिली दरार

जिस स्थान पर दरार दिखाई दी है, वह अंडरपास के ऊपर ब्रिज डेक स्लैब का हिस्सा है। इसके नीचे करीब 30 फीट की गहराई है। जांच के लिए दरार वाली जगह के आसपास करीब दो वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क खोदी गई है।

प्रभावित हिस्से की सुरक्षा के लिए ग्रीन नेट भी लगाया गया है। नई दिल्ली जाने वाली चार लेन में से पहली और दूसरी लेन को कुछ दूरी तक बंद किया गया है। फिलहाल तीसरी और चौथी लेन से वाहनों को निकाला जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सुधार कार्य पूरा होने और सामान्य आवाजाही बहाल होने में करीब एक सप्ताह लग सकता है।

2019 में शुरू हुआ था निर्माण

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में इसका करीब 244 किलोमीटर हिस्सा वर्ष 2023 में बनकर तैयार हुआ। ऐसे में महज तीन साल में अंडरपास के ऊपर सड़क के हिस्से में खराबी सामने आने से एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है। इससे गुजरात और महाराष्ट्र से आने-जाने वाले वाहनों का दबाव इस मार्ग पर और बढ़ने की संभावना है।

तीन साल में ही सामने आई खामियां

एनएचआई के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेन्द्र चापेकर ने बताया कि यह कार्य नियमित निरीक्षण और प्रो-एक्टिव मटेनेंस व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान ब्रिज डेक स्लैब के करीब दो वर्गमीटर हिस्से में खराबी मिली थी। ब्रिज के हिस्से से पानी रिस रहा था। सुस्था को देखते हुए सुधार कार्य कराया जा रहा है। फिलहाल मार्ग पर ट्रैफिक कम होने के कारण काम सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है। इसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में मिला ड्राइवर का शव

माही की गूंज, रतलाम।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 के बाहर मालवा रैस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे खड़ी बुलेरो कार में बुधवार सुबह ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वाहन मालिक प्रेमसिंह पुत्र उमराव सिंह रावत ने सुबह करीब 9.30 बजे जीआरपी चौकी पर सूचना दी कि उनकी बुलेरो कार क्रमांक एमपी-43-28-9255 की बीच वाली सीट पर चालक 37 वर्षीय हिम्मत सिंह पुत्र दातार सिंह मृत अवस्था में पड़ा मिला।

जीआरपी ने कार की जांच की तो हिम्मत सिंह का शव अंडरवियर में

बीच वाली सीट पर मिला। कार में उसके कपड़े, पानी की बोतल और जहरीले पदार्थ के तीन पाउच मिले। कार के अंदर और बाहर उल्टी भी मिली है। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद जीआरपी ने शव को करीब 11.15 बजे ऑटो रिक्शा से मेडिकल कॉलेज भेज दिया।

तीन दिन से घर नहीं गया था

प्रारंभिक जांच में हिम्मत सिंह के पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। उसकी पत्नी वंदना के अनुसार वह तीन दिन से घर नहीं गया

था। रेलवे में वाहन अटैच होने के कारण वह अक्सर ड्राइविंग के काम से बाहर रहता था। वाहन मालिक प्रेमसिंह ने बताया कि उनकी गाड़ियां रेलवे में अटैच हैं और हिम्मत पिछले करीब तीन साल से उनकी बुलेरो चला रहा था।

हिम्मत सिंह का स्थायी पता 346/सी जवाहर नगर रतलाम और वर्तमान पता बंगला नंबर 1686, रोड नंबर 8, ओल्ड रेलवे कालोनी रतलाम बताया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार, जीआरपी चौकी प्रभारी रामपाल इवने और एसएसएल अधिकारी डॉ. अतुल मित्तल मौके पर पहुंचे।



शिनाख्त होने के बाद हिम्मत की पत्नी, मां और अन्य स्वजन भी मौके पर पहुंचे। जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने

की बात सामने आई है। कार से जहरीले पदार्थ के पाउच भी मिले हैं। मामले में मर्ग कायम कर सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

अतिथि शिक्षक के साथ बर्बरता, छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप

माही की गूंज, रतलाम। ताल थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों द्वारा अतिथि शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना 3 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग शिक्षक को पेड़ से बांधकर चाटे मारते और रस्सी से पीटते दिखाई दे रहे हैं।

शिक्षक रो-रो कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक शिक्षक पेड़ से बंधा नहीं मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक

मुरैना जिले के कैलास थाना क्षेत्र के ग्राम शाहदपुर निवासी 21 वर्षीय योगेंद्र पुत्र रघुवीर सिंह जाटव खारवाकला चौकी क्षेत्र के पिपलिया तुखार के शासकीय प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक हैं। वह पिछले करीब चार माह से यहां पढ़ा रहा है। इससे पहले वह कोटड़ी के पास मंडावल में अतिथि शिक्षक था।

वर्तमान में खारवाकला में किराये के मकान में रहता है। ग्रामीणों के अनुसार योगेंद्र 3 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल से लंच के समय करीब 15 किमी दूर रहने वाली एक छात्रा से मिलने पहुंचा था। इसकी जानकारी छात्रा के स्वजनों को हो गई।

छात्रा को झोपड़ी में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की

आरोप है कि योगेंद्र छात्रा को बहाने से बुलाकर एक झोपड़ी में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा शिक्षक को पकड़ लिया। इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो में शिक्षक को पेड़ से बांधकर कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पाँवसो एक्ट में शिक्षक गिरफ्तार, जेल भेजा

छात्रा के स्वजन की शिकायत पर योगेंद्र के खिलाफ पाँवसो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

खारवाकला चौकी प्रभारी केएल सोनार्थी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले दो से तीन लोगों की पहचान हो चुकी है। इनमें एक छात्रा का पिता भी है। अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

मारपीट और धमकी देने की शिकायत

उधर योगेंद्र ने ताल थाने में मारपीट और धमकी देने की शिकायत की है। इसमें बताया कि वह दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल से लंच के समय अपनी पहचान की लड़की से मिलने गया था। करीब 2:45 बजे खारवा की कोटड़ी के पास दो लोगों ने उसे रोक लिया। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए पूछा कि वह उनके गांव की लड़की से मिलने क्यों आया है।

गाली देने से मना करने पर एक व्यक्ति ने लकड़ी और दूसरे ने रस्सी से उसके साथ मारपीट की। दोनों ने दोबारा गांव की किसी लड़की से मिलने आने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

काले सोने की खेती की लागत बढ़ी, किसानों को दाम मिल रहे पुराने



किसानों के धरने पर जाकर घोषणा की थी कि अब सरकार अफीम के दाम पांच हजार रुपये प्रतिकिलो देगी। इससे किसान भी खुश हुए और सांसद का कई गांवों में स्वागत कर साफे भी बांधे।

हालांकि, उसके बाद नौ साल हो गए हैं। हर साल अफीम की तुलनाई हो रही है पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम 850 रुपये से अधिकतम 3500 रुपये प्रतिकिलो के दाम ही तय कर रखे हैं पर किसानों को औसत दाम 1100-1200 रुपये प्रतिकिलो ही मिल रहे हैं।

जब पढ़े मार्फीन के आधार पर तो दाम अफीम पर क्यों

संतोष पाटीदार बालागुड़ा, पुष्कर पाटीदार, रामेश्वर शर्मा, बद्रीलाल धनगर, राहुल पाटीदार दलौदा रेल, शांतिलाल पाटीदार धमनार, राधेश्याम पाटीदार दलौदा रेल, अनिल शर्मा जवासिया, राजेश शर्मा जवासिया, राजेश पाटीदार ने बताया कि विभाग द्वारा मार्फीन के प्रश को आधार मानकर पड़े दिए जा रहे हैं जबकि मूल्य देते समय अफीम की गढ़ता को आधार मान रहे हैं।

जब मार्फीन का आधार मानकर लाइसेंस दिये जा रहे हैं तो किसानों को उपज का मूल्य भी इसी आधार पर दिया जाना चाहिए। उच्च क्वालिटी की अफीम के भाव 3500 रुपये आज तक किसी किसान को नहीं दिए गए हैं। यह केवल दिखावा मात्र है। किसानों को उच्च क्वालिटी की अफीम के

1460 रुपये से लगाकर 1800 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। इस भाव से अफीम लेकर किसानों को ठगा जाता है। अफीम नीति निर्धारण में राजनीति को दूर रखकर किसानों उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

गांवों में पट्टाधारी किसान का

अलग ही सम्मान

अंग्रेजों के शासनकाल में मंदसौर क्षेत्र और इससे सटे राजस्थान के चित्तौड़, कोटा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ में अफीम की खेती शुरू की गई थी। समशीतोष्ण जलवायु अनुकूल होने से सर्वाधिक 20 हजार से अधिक पट्टे मंदसौर जिले में हैं। गांवों में अफीम पट्टाधारी किसान को अलग सम्मान मिलता है इसलिए वह कड़कें की सड़ों में रात में खेतों में रखवाली करते हैं। डोडे में चीरा लगाने से पहले मां कालिका की पूजा करते हैं। जब से रुपये लगाकर अफीम की खेती करते हैं। बाजार में अफीम के सह उत्पाद पोस्ता दाना के भाव 2000 रुपये किलो तक हो गए हैं पर सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए।

किसान परेशान दुखी

यह केंद्र सरकार की फसल है। पर 2009 के बाद अभी तक दाम नहीं बढ़े हैं। जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को प्रतिवर्ष बोनस और महंगाई भता मिलता है उसी प्रकार अफीम काश्तकार को फसल का निशुल्क बीमा एवं बोनस का लाभ मिलना चाहिए। जो काश्तकार फसल की अच्छी

नाथ आवेदक से 8000 रुपये लेने पर सहमत हो गया था और 2000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद मंगलवार को ट्रैप दल का गठन कर गोरधन माली की 6 हजार रुपये लेकर भेजा।

दल ने डिगांव-बसई मार्ग पर रूपनी चौराहे पर होटल रुद्राक्ष पर 6,000 रुपये की रिश्त लेते आरोपित दीपक नाथ कम्प्यूटर ऑपरेटर को पकड़ लिया। ट्रैप कार्रवाई में डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हिना डाबर और प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक श्याम शर्मा, मोहम्मद इसरार, उमेश जाटव सहित 10 सदस्यों की टीम शामिल रही।

काले सोने की खेती की लागत बढ़ी, किसानों को दाम मिल रहे पुराने

उपज देता है उसका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना चाहिए। आज भाव सही और नीति स्पष्ट नहीं होने से किसान परेशान और दुखी है। - योगेंद्र जोशी, आनंदोड़ा

लागत नहीं निकल रही है

अफीम के खेत में 15-20 दिन की लुणी चिरनी का खर्च ही 50 हजार रुपये तक होता है। खाद-बीज, हंकाई, जुताई, निदाई-गुदाई वह सभी अलग हैं। विभाग किसानों से 870 रुपये किलो की न्यूनतम दर पर खरीदता है। इससे तो लागत भी नहीं निकल रही है। - कालीलाल पाटीदार, आनंदोड़ा

टेरिफ कमीशन की मांग

अफीम किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी कुछ कार्य किया है। कई लोगों के कटे हुए पट्टे बहाल भी कराए हैं। अफीम के दाम बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के टेरिफ कमीशन तक मांग की जा चुकी है। जल्द ही इसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। - सुधीर गुप्ता, सांसद

10 हजार रुपये किलो मिले

ग्राम दौरवाड़ा के खूबचंद शर्मा ने बताया कि अफीम फसल में लागत अधिक है। कुल मिलाकर 10 आरी में अब 80 से 90 हजार रुपये तक खर्च आता है। लागत के आधे भाव भी नहीं मिलने से किसान परेशान और दुखी है। अफीम के भाव न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति किलो से प्रारंभ किए जाए ताकि किसानों को उसकी लागत मूल्य का भाव मिल सके।

नगर निगम में घुसे कांग्रेसी, लहराया झंडा, जमकर की नारेबाजी

माही की गूंज, खंडावा।

शहर की मूलभूत समस्याओं और नगर निगम की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को नगर निगम का घेराव किया। गांधी भवन से रैली के रूप में पहुंचे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए निगम परिसर में दाखिल हो गए। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

ज्ञापन लेने के लिए निगम आयुक्त प्रियंका राजावत के मौके पर नहीं पहुंचने पर कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। काफी देर बाद आयुक्त के पहुंचने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा खुवंशी ने ज्ञापन का वाचन किया।

प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष दीपक श्मूल्हूश, राठौर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा खुवंशी,

जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपालसिंह पुरनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. मुनीश मिश्रा सहित कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने 25 साल से भाजपा का महापौर, फिर भी खंडवा बेहल नारे के साथ आंदोलन किया।

कांग्रेस नेताओं ने पेयजल, जर्जर सड़क, नाली, सीवरेज, सफाई, पार्किंग और नगर निगम से जुड़े आम लोगों के कामकाज की समस्याएं उठाईं। राठौर ने आरोप लगाया कि जनता के कर से मिलने वाले पैसे की बर्बादी हो रही है। उन्होंने निगम कर्मचारियों की एनपीएस राशि में गड़बड़ी और बिना पैसे दिए काम नहीं होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने 252 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना पर सवाल उठाते हुए कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की जांच की मांग की।

प्रतिभा खुवंशी ने कहा कि खंडवा में 25 साल से भाजपा का महापौर होने के बावजूद लोगों को साफ पानी, अच्छी सड़क

और बेहतर नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाते हुए करीब 42 हजार मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा किया और इसे लेकर भी सवाल उठाए।

वहीं निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि शहर में विकास कार्य जारी हैं। सीवरेज योजना का

काम स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार किया जा रहा है और कार्य की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ है और

सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा ज्ञापन में रखी गई मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया।



भतीजा-भतीजी को सरकारी स्कूल में तीसरी और पांचवीं पास दिखाने का आरोप

माही की गूंज, बड़वानी।

सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड में कथित फर्जीबाड़े का मामला सामने आया। राजपुर तहसील के ग्राम बुदरा निवासी कमल सोलंकी ने आरोप लगाया कि गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने उनके भाई के बच्चों को बिना स्कूल आए और परीक्षा दिए ही कक्षा में पास दर्शा दिया। जबकि दोनों बच्चे इंटीर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और बुदरा के स्कूल में कभी दाखिल ही नहीं हुए।

कमल सोलंकी के अनुसार उनका भतीजा रोशन सोलंकी वर्ष 2025-26 में इंटीर के सिटी पब्लिक

स्कूल में कक्षा तीसरी में पढ़ रहा था। इसके बावजूद बुदरा के शासकीय स्कूल के अभिलेख में उसे कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण दर्शाया गया। वहीं उनकी भतीजी श्रेया इंटीर में कक्षा पांचवीं में पढ़ रही है, लेकिन उसका नाम भी बुदरा स्कूल के अभिलेख में दर्ज कर दिया गया।

कमल सोलंकी ने बताया कि बुदरा स्कूल के शिक्षक पांचवीं बडोले ने बच्चों के प्रवेश पत्र और अंकसूची उन्हें दी थी। उन्होंने यह



लाछी परीक्षा केंद्र पर उनकी ओर से पांचवीं की परीक्षा किसने दी? उपस्थिति का सत्यापन किसने किया और अंकसूची किस आधार पर जारी की गई? शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अभिलेखों में फर्जी विद्यार्थियों के नाम जोड़कर छात्र संख्या बढ़ाई गई, जिससे छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और गणवेश की राशि में भी गड़बड़ी की आशंका है।

कमल सोलंकी ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री

हेल्पलाइन और जिला प्रशासन से भी की है। उनका आरोप है कि राजपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी की टीम ने अब तक मौके पर पहुंचकर जांच नहीं की। उन्होंने शिकायत को दबाने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि विकासखंड स्तर के बजाय जिला स्तर की स्वतंत्र टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही लाछी परीक्षा केंद्र के अभिलेख सुरक्षित किए जाएं और दोषी पाए जाने पर शिक्षक पांचवीं बडोले के खिलाफ निलंबन सहित कानूनी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने अवैध शराब की 7 पेटियां पकड़ी

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बीजासन गांव में ग्रामीणों ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल से ले जाई जा रही अवैध शराब की सात पेटियां पकड़ीं। ग्रामीणों ने एक युवक को भी पकड़कर पुलिस और आबकारी विभाग को सूचना दी। उनका आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री और तस्करी जारी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा।

प्रत्यक्षदर्शी संजय वास्करले के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि बड़वानी की ओर से मोटरसाइकिल पर शराब की पेटियां बीजासन लाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश मार्ग पर घेराबंदी कर बाइक सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा।

ग्रामीणों के अनुसार जब शराब में सफेद प्लेन, केन बीयर सहित अन्य ब्रांड की शराब शामिल है। सूचना देने के बाद भी सुबह 9.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक



करीब छह घंटे तक पुलिस और आबकारी विभाग का अमला मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है।

पकड़े गए युवक संदीप अलावे ने ग्रामीणों को बताया कि वह पिछले कई महीनों से शराब सप्लाई का काम कर रहा है। उसके अनुसार वह बड़वानी बस स्टैंड स्थित शराब दुकान से सुबह-शाम मोटरसाइकिल के जरिए बीजासन और मोरकट्टा गांवों में शराब पहुंचाता था।

गांव निवासी मानक ने बताया कि शराबबंदी की मांग को लेकर ग्रामीण दो बार कलेक्टर की जनसुनवाई और आबकारी कार्यालय में आवेदन द चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने अब निर्णय लिया है कि गांव में न तो शराब बिकने देंगे और न ही गांव के रास्ते से शराब ले जाने देंगे। वहीं संपर्क करने पर पुलिस और आबकारी अधिकारियों ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया।

प्रताड़ना मामले में ससुराल पक्ष के 13 लोगों पर प्रकरण

माही की गूंज, खरगोन।

कसरावद की एक महिला ने पति, देवर समेत ससुराल पक्ष के 13 लोगों पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर महाराष्ट्र के दोंडाईचा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने महिला के पति स्वतंत्र जैन और देवर नेमिश जैन को हिरासत में लिया है।

पंडिता लक्ष्मी जैन का मायका दोंडाईचा में है। उसकी शिकायत के बाद दोंडाईचा पुलिस की टीम जांच के लिए कसरावद पहुंची थी। लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि ससुराल में करीब 14 वर्षों से उसे परेशान किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं ससुराल पक्ष के परिवार प्रमुख अनिल जैन ने महिला के आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि लक्ष्मी को परिवार में बेटी की तरह सम्मान दिया गया और उसके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि लक्ष्मी अपने साथ 350 ग्राम से अधिक सोना लेकर गई थी। जांच अधिकारी सौरभ ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



माही की गूंज, बड़वानी।

शहर के मोटी माता मंदिर के सामने स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थल पर नगर पालिका द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष एवं राजपूत समाज के राकेश सिंह जाधव ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले



को लेकर समाज में नाराजगी है। राकेश सिंह जाधव ने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजपूत समाज द्वारा स्थापित की गई थी। नगर पालिका ने करीब तीन माह पूर्व प्रतिमा स्थल के सामने सजावटी निर्माण कार्य कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि खंभों की वेलिंडा सही ढंग से नहीं की गई है, जिसके कारण वे हल्का दबाव पड़ने पर भी हिल रहे हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर तार टूटने तथा जालियां गिरने या गायब होने की बात भी सामने आई है।

नेता प्रतिपक्ष ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली और ठेका व्यवस्था पर

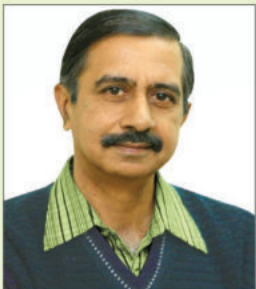
भी प्रश्न उठाए। उनका आरोप है कि प्रकाश व्यवस्था, सामग्री आपूर्ति और ठेके का कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रभारी इंजीनियर ने किस गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर कार्य और भुगतान को स्वीकृति दी। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप सभी समाजों के प्रेरणास्रोत हैं, इसलिए प्रतिमा स्थल पर उच्च गुणवत्ता का कार्य होना चाहिए था।

वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निहू चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य प्लेस्ट से बेस्ट अवधारणा पर आधारित है। शहर से

निकलने वाली अनुपयोगी सामग्री का उपयोग कर स्थल को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पुराने पोल के साथ नया पोल लगाकर कार्य किया गया, जिससे पालिका का खर्च कम हुआ।

अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी स्थान पर पोल हिलने की शिकायत है तो उसकी जांच कर आवश्यक सुधार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज और नगर पालिका के बीच पूरा समन्वय है तथा सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों ने समाज और पालिका के बीच विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

बढ़ती ग्लेशियर झीलों से सुरक्षा-पेयजल संकट की आहट



मुकुल थापा

पिघलते ग्लेशियर ऊंचे हिमालय के स्वरूप को बदल रहे हैं। वहां ग्लेशियर झीलों तेजी से बढ़ रही हैं और उनका आकार भी फैल रहा है। जलवायु परिवर्तन दरअसल दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों को बदल रहा है, इसलिए इस बदलाव पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। एक नए अध्ययन में हिमालय में हो रहे परिवर्तन का खुलासा किया गया है। यह अध्ययन प्राग की चार्ल्स यूनिवर्सिटी की रिसर्चर आयुषी पांडे ने किया है। लगभग 30 सालों के उपग्रह पर्यवेक्षण के आधार पर पांडे ने 1994 और 2023 के बीच भारत के पश्चिमी हिमालय में अलकनंदा बेसिन की 74 ग्लेशियर झीलों में हुए बदलावों को ट्रैक करने के लिए लैंडसैट और सेंटिनल-2 की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इससे जो तस्वीर हमारे सामने आती है, वह तेजी से बदलते लैंडस्केप की है। जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका पिघला हुआ पानी अधिक ऊंचाई वाली झीलों को भरता है और नई झीलें बनाता है। सही हालात होने पर ये झीलें एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकती हैं।

अध्ययन से पता चला कि हिमालय में पुरानी झीलें बढ़ रही हैं और नई झीलें बन रही हैं। अध्ययन में शामिल 0.01 वर्ग किलोमीटर से बड़ी 24 ग्लेशियर झीलों में झीलों का कुल क्षेत्रफल 1994 में 0.97 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 तक 1.62 वर्ग किलोमीटर हो गया। यह सिरफ़ तीन दशकों में

67 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। लेकिन मौजूदा झीलों का बढ़ना ही सब कुछ नहीं है। अध्ययन में 57 बिल्कुल नई ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई, जो अध्ययन के दौरान बनीं, जिससे अलकनंदा बेसिन में कुल झीलों की संख्या 131 हो गई। इन नई झीलों में से 18 झीलें पहले ही 0.01 वर्ग किलोमीटर के पैमाने से बड़ी हो चुकी हैं। कुछ झीलों तो चौकाने वाली रफ़्तार से फैली हैं। वसुंधरा झील 1994 और 2023 के बीच 261 प्रतिशत बढ़ी। इसी दौरान बलबाला झील 119 प्रतिशत बढ़ी।

मुख्य आंकड़ों के अलावा, अध्ययन में 27 ऐसी ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई, जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। इनमें बद्रीनाथ के ऊपर की ओर स्थित एक झील भी शामिल है। वसुंधरा झील के तेजी से फैलने पर विशेष रूप से बारीकी से ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। ग्लेशियर वाली झील के आकार और स्थिरता में बदलाव का सीधा असर नीचे के इलाकों पर पड़ सकता है। रिसर्चर का कहना है कि इन झीलों की लगातार निगरानी और आगे और ज्यादा विस्तार से जांच की जरूरत है।

दरअसल, मुख्य चिंता ग्लेशियर झीलों में अचानक बाढ़ को लेकर है। इस तरह की बाढ़ को 'ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट



फ्लड' (जीएलओएफ) भी कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है, जब बर्फ, चट्टान या मलबे से रुकी हुई पानी की भारी मात्रा अचानक छूट जाती है और पानी, कीचड़ और मलबे को बहुत तेज और विनाशकारी ताकत के साथ नीचे की ओर बहा ले जाती है।

यह अध्ययन ऐसे समय में आया है, जब नेपाल में 26 अगस्त, 2026 को आई भयानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। वह आपदा कोई आम जीएलओएफ नहीं थी, लेकिन इसने दिखाया कि ऊंचे पहाड़ों

में अचानक आने वाली बाढ़ के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। आयुषी पांडे ने कहा, 'हाल की बाढ़ इस बात की याद दिलाती है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों की लगातार निगरानी कितनी जरूरी है, जहां भारी बारिश, ग्लेशियर झील का बढ़ना, ढलान का अस्थिर होना और भूकंप जैसी कई आपदाएं एक साथ मिलकर नीचे के इलाकों पर असर को और बढ़ा सकती हैं।' उन्होंने कहा, 'बड़े और दुर्गम इलाकों की जांच-पड़ताल के लिए उपग्रह डेटा बहुत काम का होता है। इससे हम नई बनी झीलों की पहचान कर सकते हैं, झील के आकार में बदलाव को माप सकते हैं, तेजी से बढ़ रही झीलों का पता लगा सकते हैं और उन झीलों को चुन सकते हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जरूरत है। इस काम के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट और आर्थिक मदद की जरूरत है, जिसमें सीमाओं के पार वैज्ञानिक सहयोग और डेटा शेयरिंग भी शामिल है। इसे एक साझा क्षेत्रीय चिंता के तौर पर देखा जाना चाहिए।'

यह आखिरी बात ही इस चुनौती की असल जड़ है। हिमालय कई देशों में फैला हुआ है। किसी एक देश के पहाड़ों में बनने या बढ़ने वाली ग्लेशियर वाली झील अपनी सीमाओं

से दूर के समुदायों और बुनियादी ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ इस बात का एक बड़ा दहशतपूर्ण है कि कैसे ऊंचे पहाड़ों से जुड़ा खतरा तेजी से मानवीय संकट में बदल सकता है। नए सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि उत्तर भारत के पहाड़ों में भी इसी तरह के खतरे चुपचाप बढ़ रहे हैं।

फिलहाल, यह स्टडी शोधकर्ताओं को कुछ ऐसी जानकारी देती है, जो उन्हें इस दुर्गम और मुश्किल इलाके में शायद ही कभी मिलती है। इस स्टडी से तीन दशकों का यह स्पष्ट रिकॉर्ड मिला है कि जमीन का स्वरूप ठीक कहां और कितनी तेजी से बदल रहा है। अगली तेजी से फैलती झील समुदायों को बचने का ज्यादा मौका नहीं देगी।

इस बीच, इस महीने जारी एक अन्य स्टडी के अनुसार, हिमालय एक अहम मोड़ पर पहुंच रहा है, क्योंकि ग्लेशियर एक दशक पहले की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। इससे जल सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। क्या इस जानकारी से यह तथ्य करने में मदद मिल सकती है कि यह इलाका खतरों से निपटने के लिए कितना तैयार है। अगली तेजी से फैलती झील समुदायों को बचने का ज्यादा मौका नहीं देगी।

इस बीच, इस महीने जारी एक अन्य स्टडी के अनुसार, हिमालय एक अहम मोड़ पर पहुंच रहा है, क्योंकि ग्लेशियर एक दशक पहले की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। इससे जल सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। क्या इस जानकारी से यह तथ्य करने में मदद मिल सकती है कि यह इलाका खतरों से निपटने के लिए कितना तैयार है। अगली तेजी से फैलती झील समुदायों को बचने का ज्यादा मौका नहीं देगी।

देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर गोबर करती दिखी भैंसें

भोपाल।

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को देश के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में शुमार किया जाता है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का दावा किया जाता है, उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भैंसों के घूमने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। प्लेटफॉर्म पर दो भैंसें ट्रेन के बिल्कुल बगल से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दो भैंसें प्लेटफॉर्म पर आराम से टहल रही हैं और यात्रियों के बीच से होते हुए ट्रेन के पास तक पहुंच गईं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर भैंसें प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचीं?

450 करोड़ के स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से

पुनर्विकास किया गया है। इसे देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों में शामिल किया गया है।

स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, एस्केलेटर, लिफ्ट, एसी लाउंज, फूड कोर्ट और आधुनिक यात्री सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर आवारा पशुओं के पहुंचने का वीडियो सामने आने के बाद करोड़ों रुपये की लागत से तैयार स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

रेलवे बोला- मामले को दिखवा रहे हैं

मामले को लेकर जनसंपर्क अधिकारी शिव शंकर शाह ने कहा कि वह पूरे मामले को दिखवाएंगे। उन्होंने बताया कि रानी कमलापति स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे और बंसल के पास है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक सामने आती है तो रेलवे, बंसल के साथ मिलकर उसे सुधारने का काम करता है।

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार आउटर की तरफ का हिस्सा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से जानवर स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे



पटरी के आसपास लोग खाने-पीने का सामान भी फेंक देते हैं। खाने की तलाश में जानवर रेलवे ट्रैक और स्टेशन की तरफ आ जाते हैं।

यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

हालांकि रेलवे का तर्क अपनी जगह है,

लेकिन सवाल यह है कि अगर एक भैंस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकती है तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों लगातार आती-जाती हैं और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद रहते हैं। ऐसे में किसी आवारा पशु के अचानक ट्रेन की चपेट में आने या यात्रियों से टकराने की स्थिति में बड़ा हादसा

हो सकता है।

फिलहाल रेलवे ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने की बात कही है। अब देखना होगा कि भैंसें स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचीं और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए रेलवे और स्टेशन यात्रियों से टकराने की स्थिति में बड़ा हादसा

विकसित भारत

संकल्प सभा आयोजित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में +25 साल जनसेवा से राष्ट्रसेवा+ के अंतर्गत +विकसित भारत संकल्प सभा+ एवं +सेवा ज्योति यात्रा+ कार्यक्रम का आयोजन समाधि स्थल आलीराजपुर में किया गया।

कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा देखा एवं सुना गया। कार्यक्रम स्थल पर जिला विकास पुस्तिका का वितरण किया गया। पुस्तिका के माध्यम से जिले में विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों तथा उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई।

कार्यक्रम में सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हजरी बाई खरात, जनप्रतिनिधि मकू परवाल, रिकेश तंवर, गोविंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थितजनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण, सुशासन एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।



रावण दहन का विरोध

माही की गूंज, उज्जैन।

20 अक्टूबर को देशभर में दशहरा का पर्व भूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी रावण दहन करते हैं। लेकिन उज्जैन में इस बार नजारा कुछ और नजर आ रहा है। दरअसल अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन का विरोध करने का ऐलान किया है।

शहर में चार प्रमुख रावण दहन के स्थान हैं। जहां संगठन की ओर से आयोजन को वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। संगठन का कहना है कि ये दहन शास्त्र सम्मत नहीं है

और इसे बंद करने की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

आयोजकों को भेजे नोटिस

दशहरा मैदान, कार्तिक मेला ग्राउंड, नानाखेड़ा और शास्त्री नगर शहर में चार जगह रावण दहन किया जाता है। इन चारों जगह के आयोजकों को कानून नोटिस भेजे गए हैं। संगठन का कहना है कि रावण के पुतले को मनोरंजन के तौर पर लोगों के सामने पेश करना अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि रावण के कर्मों की सजा भगवान राम उसे दे चुके

हैं। अब पुतले का दहन करने की परंपरा जारी रखने का औचित्य नहीं है।

पीएम और सीएम को भी लिखा पत्र

आयोजकों को कानूनी नोटिस देने से पहले संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर चुका है। केवल उज्जैन में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी संगठन की ओर से रावण का गुणगान



करते हुए पोस्टर लगाए गए थे।

पिछले साल भी हुआ था विरोध

यह पहली बार नहीं है जब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज दशहरा पर्व पर रावण दहन का विरोध कर रहा है।

पिछले साल विरोध देखने को मिला था। संगठन ने मुख्य आयोजन से पहले पुतले के सामने रावण के जयकारे लगाए थे। इतना ही नहीं मटकियां फोड़कर रावण दहन रोकने की मांग भी की गई थी।

उज्जैन विकास प्राधिकरण

ने किसानों को दिया 16

करोड़ का मुआवजा

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन विकास प्राधिकरण ने अपना वादा निभाते हुए मंगलवार को सिंहस्थ अंतर्गत बनने वाली 50 किलोमीटर लम्बी सड़कों के हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा 16 करोड़ रुपए 32 किसानों को वितरित किया। भूमि को आपसी सहमती से अधिग्रहण किया गया था।

विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. रवि सोलंकी ने बताया कि इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नगर भाजपाध्यक्ष संजय अग्रवाल उपस्थिति थे। श्री सोलंकी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों के हितों का ध्यान रखना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा समय पर मिले, इसके लिए प्राधिकरण लगातार काम कर रहा था।

उन्होंने बताया कि सभी पात्र किसानों को उनकी राशि सौंप दी गई है। मुआवजा प्राप्त करने के बाद किसानों ने प्राधिकरण की इस त्वरित व पारदर्शी कार्रवाई पर सतोष व्यक्त किया व आभार माना। प्राधिकरण द्वारा आने वाले दिनों में शेष बचे किसानों के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें भी जल्द से जल्द मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर प्राधिकरण के विधि अधिकारी मनीष जोशी, संपदा अधिकारी जीवनलाल मोधी, कार्यपालन यंत्री कुलदीप रघुवंशी एवं शुभम सोनी सहित कार्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।

एंबुलेंस ने दो कार को मारी टक्कर

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन-जावरा स्टेट हाईवे पर उन्हेल थाना क्षेत्र में मंगलवार एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नागझिरी-नागदा रोड पर स्थित साईं कृपा ढाबे के पास तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित एंबुलेंस ने आगे चल रही दो अटिंगा कारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद बेकाबू एंबुलेंस सड़क से नीचे उतरकर दीपक चौहान मंगलवार सुबह अपनी अटिंगा कार से किसी काम से इंदौर जा रहे थे। रास्ते में उनके आगे एक और अटिंगा कार चल रही थी। सुबह करीब 10

बजे जैसे ही वे साईं कृपा ढाबे के पास पहुंचे, तभी उज्जैन की तरफ से आ रही तेज रफतार एंबुलेंस चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पहले आगे वाली कार को टक्कर मार दी। पहली गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बेकाबू एंबुलेंस ने पीछे चल रही दीपक चौहान की कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दीपक के दाहिने हाथ की कलाई पर चोट आई है। वहीं उनकी कार के दोनों गेट, रियर व्यू मिरर, डिक्की, टायर और पीछे का कांच क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दूसरी कार के गेट और चेसिस को भारी नुकसान पहुंचा है।

बच गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और एंबुलेंस चालक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची उन्हेल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और फरार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल, पुलिस के अनुसार नागदा की दयानंद कॉलोनी में रहने वाले दीपक चौहान मंगलवार सुबह अपनी अटिंगा कार से किसी काम से इंदौर जा रहे थे। रास्ते में उनके आगे एक और अटिंगा कार चल रही थी। सुबह करीब 10

टंडी चाय गर्म करो, बबीता मैम शर्म करो

भोपाल।

प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में स्थित नवीन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर सोमवार को उस समय माहौल गरमा गया, जब 11वीं कक्षा (मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम) के दर्जनों छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। छात्रों ने एक महिला साईंस टीचर पर फेल करने की धमकी देने, प्रोजेक्ट के नाम पर हर महीने पैसे ऐंठने, सीनियर छात्रों को लोहे के पाइप से पीटने और स्कूल में मजदूरी की तरह काम कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, छात्रों के उग्र प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए शिक्षा विभाग तुरंत हस्तक्षेप में आया। जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी टीचर का दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया है और उनकी जगह नए फिजिक्स टीचर की नियुक्ति कर दी है।

रविवार को बुलाकर कराते थे सफाई और बेंच शिफ्टिंग

मुख्य रूप से 11वीं कक्षा के छात्रों का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर को ही प्रिंसिपल को लिखित शिकायत दी थी। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में आयोजित होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान उनसे जबरन कर्मचारियों की तरह काम लिया जाता था।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, हम स्कूल में पढ़ाई करते आते हैं, कर्मचारियों की तरह मजदूरी करने नहीं। हमसे रविवार के दिन भी स्कूल बुलाकर बेंच लगावाई जाती थी, परिसर की सफाई कराई जाती थी और रोल नंबर लिखवाए जाते थे। मना करने या मांग न मानने पर हमें फेल करने की धमकी दी जाती थी। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि टीचर क्लास में मोबाइल चलाने में व्यस्त रहती थीं और प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर हर महीने पैसे मांगती थीं।

उनका कहना था कि टीचर खुलेआम कहती थीं कि 'साईंस सिर्फ वही पढ़े जो इसका खर्च उठा सकते हैं।' इसके अलावा सीनियर छात्रों को उनके सामने लोहे के पाइप से पीटने का भी आरोप लगाया गया।

पुलिस की दखल के बाद 4 घंटे में बना समझौता

हंगामे की सूचना मिलते ही मिसरोद पुलिस स्टेशन के प्रभारी विमलेश कुमार राय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छात्रों और स्कूल प्रबंधन के बीच मध्यस्थता कराई। लगभग 4 घंटे चली लंबी बातचीत के बाद छात्रों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे छात्र अपनी-अपनी कक्षाओं में लौटे। प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने 'ठंडी चाय गर्म करो, बबीमा मैम शर्म करो' जैसे नारे लगाए।



मामले पर जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने बताया, "संबंधित टीचर का तबादला दूसरे स्कूल में कर दिया गया है और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए नए फिजिक्स टीचर को नियुक्त कर दिया गया है। टीचर पर लगे सभी गंभीर आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दो दिनों के भीतर सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच पूरी कर आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।"

नतीजे सुधारने के लिए बरतती थी सख्ती

दूसरी ओर, आरोपी शिक्षिका बबीता कुशवाहा ने

अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वह 1999 से अध्यापन कार्य कर रही हैं और 2010 से इस स्कूल में पदस्थ हैं।

फिजिक्स विषय में बेहतर परीक्षा परिणाम लाने के लिए वह छात्रों के साथ थोड़ी सख्ती बरतती थीं। उन्होंने पास या फेल करने के बदले पैसे मांगने, वसूली करने और सफाई कराने जैसे सभी आरोपों का खंडन किया है।

बता दें कि 1962 में स्थापित नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल में कुल 37 स्टाफ सदस्य हैं, जहां अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षा विभाग जांच में जुट गया है।

कृमि मुक्ति दिवस पर अभियान का शुभारंभ

माही की गूंज, आलीराजपुर।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने छात्राओं को कृमिनाशक दवा पिलाकर किया। अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। छूटे हुए हितग्राहियों को 9 अक्टूबर 2026 माँप-अप दिवस पर दवा दी जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने स्वच्छता एवं स्वस्थ आदतें अपनाने का संदेश देते हुए नाखून साफ रखने, भोजन से पहले एवं शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने, स्वच्छ पानी पीने, खुले में शौच से बचने तथा फल-सब्जियों को साफ पानी से धोकर उपयोग करने की अपील की। स्वास्थ विभाग के अनुसार कृमि संक्रमण से बच्चों में कुपोषण, खून की कमी, थकान तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। अभियान के सफल क्रियाकव्यन में आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ विभाग का मैदानी अमला सक्रिय रूप से कार्य करेगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश अतुलकर सहित स्वस्थ विभाग का जमीनी अमला मौजूद था ।



जिले में गौ-हत्या का कारण क्षेत्रवासियों का खुला और मौन समर्थन या स्वीकृति तो नहीं...?

पुलिस की नाक के नीचे वर्षों से चल रहा गौकशी का अवैध बूचड़ खाना, आखिर आदिवासी संगठन के लोगों ने आनक से क्यों किया उजागर?



माही की गुंज, झाबुआ।

आदिवासी बाहुल जिले में गौकशी या गौ-हत्या के मामले कोई नए नहीं हैं। ऐसे ही मामले दशकों में कई बार मीडिया की सुर्खियों में आसानी से देखने और सुनने को मिलते रहे हैं। इन सभी मामलों में अक्सर होता यही रहा है कि, गौ-हत्या हो जाने के बाद ही हंगामा होता है और पुलिस पहुंचती है। आखिर ऐसा क्यों है कि, पुलिस या प्रशासन को ऐसे मामलों की खबर पहले नहीं लगती...? या फिर जिले की पुलिस व प्रशासन गौ-हत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी नजरें पनी करना ही नहीं चाहता। जब-जब भी गौकशी के मामले उजागर होते हैं तो पीटा दिखाई देता है। जिले में हो रही इस तरह की घटनाएं पुलिस व प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करती दिखाई देती हैं। क्या पुलिस का खुफिया तंत्र इन मामलों में सूत्र हो जाता है...? या फिर पुलिस की मुखबिरी जेब भरने वाले मामलों में ही काम करती है...? हालांकि देखा जाए तो पुलिस की कार्यप्रणाली जिले में हमेशा से ही सुस्त दिखाई दी है। चाहे फिर वह चोर-उच्चकों का मामला हो या फिर डकैती का, अवैध मादक पदार्थों का

मामला हो या फिर अवैध शराब का। हमेशा से ही जिले की पुलिस व प्रशासन की कार्यप्रणाली शंका के घेरे में ही दिखाई दी है। कई मामलों में तो पुलिस 'तील का ताड़' तो राई का पहाड़ करती नजर आती है तो कई बड़े और गंभीर मामलों को 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया जाता है। ऐसे ही मामलों में एक आता है गौकशी और गौ-हत्या का खेल। पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि, जिले की पुलिस गौ-हत्या और हत्यारों के प्रति कितनी सख्त है...? गौकशी के मामलों में पुलिस मामला तो दर्ज करती है, लेकिन पकड़े जाने वाले अपराधी महज कुछ समय में ही जेल से रिहा होकर या जमानत पर फिर उसी धंधे में लग जाते हैं।

विडम्बना यह कि, गौ-हत्या के अधिकांश मामले उजागर करने में पुलिस को कोई अहम भूमिका जिले में अब तक दिखाई नहीं दी है। जिले में गौकशी के अधिकतर मामले या तो हिन्दू संगठनों द्वारा या फिर किसी सामाजिक संगठन द्वारा उजागर किये जाते रहे हैं। इस तरह के संगठन खुद अपने बूते जिले में हो रही गौ-हत्या के मामले उजागर करते हैं। मगर इसमें भी एक संदेह है जो इन संगठनों पर भी सवाल खड़े करता है। असल में जिले

में हो रही गौकशी के मामलों में अक्सर यह देखने में आया है कि, यह घटनाएं अक्सर ग्रामीण इलाकों में ही होती हैं। जब-जब इस तरह के मामले उजागर होते हैं तब-तब यह पता चलता है कि, यह काम फलों जगहों पर तो वर्षों से हो रहा था। घटना स्थल से सैकड़ों गौवंश के अवशेष भी बरामद होते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि, अचानक कोई संगठन इस तरह के मामले उजागर करता है जो लंबे समय से संचालित होते हैं। आखिर संगठन व उनसे जुड़े लोगों को लंबे समय से चल रहे गौकशी के मामलों की सूचना पहले क्यों नहीं मिलती...? और मिलती भी है तो पहले इन संगठनों व उनके लोगों को ही क्यों मिलती है...? पुलिस व प्रशासन को क्यों सीधे तौर पर इस तरह के मामलों में सूचना नहीं मिलती...? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है।

सूत्रों की माने तो ऐसा नहीं है कि, इस तरह के अधिकतर मामलों में संघ, संगठनों को अचानक से ऐसी कोई सूचना मिलती है। यह सब तो उन्हें पहले से ही पता होता है। बात तो सिर्फ सेंटिंग की है। जब तक संघ, संगठनों के पदाधिकारियों की मांग पूरी होती रहती है तब तक सबकुछ अच्छे से चलता है। जब इनकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर मामले उजागर हो जाते हैं। अधिकतर मामलों में यही होता है।

अंदरखाने की खबर रखने वाले बताते हैं कि, ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम या दबे-छुपे गौ-हत्या कर देता है। इन मामलों में गौ-हत्यारों को खुलेआम क्षेत्रवासियों का सामाजिक

संरक्षण मिलता है। गौकशी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी होती है वहां कोई ना कोई क्षेत्रवासी अपने घर या झोपड़े में गौकशी करने वालों को बकायदा जगह देता है। ऐसा नहीं है कि, गौ-हत्या करने वालों को सिर्फ एक व्यक्ति का संरक्षण होता है। बल्कि गांव के अधिकांश लोग इसे खुला और मौन समर्थन या स्वीकृति देते हैं। गांव में कोई घटना हो और किसी सरपंच को या कोटवार को या तड़वी को इसकी खबर ना हो इस जिले में ऐसा हो पाना शायद नामुमकिन है...! जब गौकशी सार्वजनिक और सामाजिक स्वीकृति या समर्थन के होती है, तो गांव में रसूख रखने वाले हर एक को उसका हिस्सा मिल जाता है। एक कहवात है कि "बकरा कटेगा तो सबमें बटेगा" बस ऐसा ही कुछ है।



नाम ना बताने की शर्त पर गौ-तस्करों के आसपास रहने वाले बताते हैं कि, यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि आप समझते हैं। बात बहुत ही पैचीदा और उलझी हुई है। सिर्फ एक अंदाजा लगाए कि जिले में कितने मवेशी बाजार लगते हैं। इनमें कितना मवेशी बिकने आता है और कितना गौवंश विकता है...? इसका हिसाब

आखिर किसके पास है...? यह कौन जानता है कि, मवेशी किसी पशु पालक ने खरीदा है या वह कटनी के लिए खरीदा गया है...? क्योंकि कटनी का माल भी इन्हीं बाजारों से खरीदा जाता है कोई आसमान से नहीं उतरता। गौवध के इस गौरख धंधे में कोई भी गौतस्कर या कसाई या खटिक खुले तौर पर मवेशियों की खरीदी नहीं करता। उनके पास इस काम के लिए कई ऐसे लोग हैं जो जिले के ही हैं और आदिवासी हैं। वे कमीशन बैस पर इन्हे मवेशी खरीदकर देते हैं। इनकी जिम्मेदारी इतनी होती है कि, ये मवेशी बाजार से खरीदकर ठेट ठिकाने तक पहुंचाते हैं। स्थानीय होने और आदिवासी या किसान होने के चलते कोई इनको रोकना तो ठीक शक भी नहीं करता।

इसके अलावा जिले की अधिकांश आदिवासी आबादी अब धर्मांतरित हो चुकी है। धर्मांतरित आदिवासी खुले तौर पर मांसहारा का समर्थक ही नहीं करते बल्कि सेवन भी करते हैं। इस स्थिति में अब यह चलन भी हो चला है कि, कहीं से खरीदने के बजाय अपने बीच के लोगों से सीधे मवेशी खरीद लिए जाए और आपस में मांस के हिस्से कर लिए जाए। जिसे स्थानीय भाषा में "बाटा पाड़ना" कहा जाता है। ऐसे मामलों में अक्सर गौमांस का ही बंटवारा होता है। मामला अपनों के बीच ही खत्म हो जाता है और किसी को इसकी खबर भी नहीं लगती। जिन गांवों में बहुसंख्यक धर्मांतरित आदिवासी रहते हैं वहां इस तरह से गौकशी होना कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जब-जब भी जिले में बड़े गौ-हत्या कांड का



पदांफास हुआ है वह इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ है। जहां धर्मांतरित आदिवासियों की संख्या बहुतायत है। चाहे फिर वह सजेली नानिया सात हो या फिर झाबुआ के समीप मोहनपुरा। यह समानता अक्सर इन मामलों में देखने को मिल ही जाती है।

मोहनपुरा गौ-हत्या कांड में जिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है उन्हे भी उसी क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्वीकृति या मौन समर्थन दिया ही होगा। क्योंकि बताया जाता है कि, इस क्षेत्र में लंबे समय से गौकशी का काम चल रहा था। लंबे समय तक इस तरह की गतिविधि बिना किसी संरक्षण, समर्थन के चल ही नहीं सकती। रही बात इस गौ-हत्या से पदांफास करने वाले संघ, संगठनों व उनके पदाधिकारियों की तो उनकी नियत यह वर्षों से चली आ रही है। कोराना काल में जब सबकुछ बंद था तब भी यहां मांस की दुकान चालू थी। उस समय ठेट झाबुआ और दूर-दूर से लोग यहां गौ मांस खरीदने आते थे। ग्रामीणों ने कभी कोई आपत्ती नहीं ली। गांव के अधिकांश लोग भी गौ मांस का सेवन करते हैं।

कुल मिलाकर जिले में हो रहे गौ-हत्या मामलों में अपराधियों को स्थानीय लोगों का खुला समर्थन और मौन स्वीकृति देखी जा सकती है। पुलिस और प्रशासन निरंक है, तो मामले उजागर करने वाले संघ, संगठन भी शंका के घेरे में हैं।

मोहनपुरा गौहत्या कांड में पांच आरोपियों पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है जिनमें से चार को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और एक आरोपी अब भी फरार है। आरोपियों के खिलाफ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4,5,9 आर्म्स एक्ट की धारा 25 (बी) और बीएनएस की धारा 325 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में भेजने के आदेश जारी किए हैं।

माही की गुंज किसी भी अपराध या अपराधी का समर्थन नहीं करता है ना ही किसी भी प्रकार के पशु वध का समर्थन करता है। बेबाकी के साथ सच लिखना और सही सूचनाओं और विचारों को अपने पाठकों तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है।

असुविधाओं और वसूली के लिए बदनाम हो चुका हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल की पो बारह

सिविल हॉस्पिटल में कुछ भी सही नहीं, डॉक्टर कलेक्टर को भी नहीं है आम मरीजों की चिंता

माही की गुंज, पेटलावद।
राकेश गोहलौत

सरकार की व्यवस्थाओं का मजाक अगर देखना है तो सिविल हॉस्पिटल पेटलावद सबसे अच्छा स्थान माना जाएगा। जहां मरीजों के स्वास्थ्य के साथ इलाज के नाम पर खिलवाड़ होता है। कहने को तो करोड़ों का भवन है, लिफ्ट, डिजिटल एक्सरा मशीन, इमरजेंसी वार्ड, ब्लड जांच, आईसीयू वार्ड सब है लेकिन सब अब असुविधा का शिकार होकर मरीज और उनके परिजनों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली फी इलाज की सुविधा भी लेनी है और मजबूरी है कि पैसा खर्च करवा के इलाज भी करवाना है। स्थिति इतनी गम्भीर हो चली है कि, पेटलावद सिविल हॉस्पिटल सिर्फ असुविधाओं और वसूली विवाद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। यहाँ मरीजों के इलाज के नाम मौजूद डाक्टरों का ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिसने अच्छे काम के लिए उनको याद किया जाए।

सवा लाख की ईसीजी मशीन तक नहीं, डायलिसिस, सोनोग्राफी मशीन हवा रही धूल

करोड़ों के सिविल हॉस्पिटल भवन में सरकारी व्यवस्था मरीजों के प्रति कितनी चिंता और कितनी सजग है इससे ही पता चलता है कि, वर्तमान में

सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज आने लगे हैं। दिल के दौरों से संबंधी मरीजों को आते ही अन्त्येष्टि कर दिया जाता है, इनकी जांच के लिए मामूली रकम सवा से डेढ़ लाख की कीमत की ईसीजी मशीन तक सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। मरीजों को पांच सौ से लेकर हजार रुपए तक केवल ईसीजी जांच के लिए खर्च निजी हॉस्पिटलों या बाहर के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। सिविल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मामले डिलेवरी के आते हैं जिसके लिए गर्भवती महिलाओं को नो माह तक सरकारी अस्पताल में जांच के लिए आना पड़ता है। और इस गर्भावस्था काल में तीन से चार बार सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है, जिससे गर्भवती महिला को डिलेवरी की स्थिति साफ होती है। भगवान भरोसे चल रहे इस सिविल हॉस्पिटल में ये सुविधा तक नहीं है।

हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है लेकिन उसके संचालन के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। और तो और यहाँ निजी हॉस्पिटलों का इतना प्रभाव है कि इस सुविधा के संचालन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। जबकि पूरे गर्भावस्था के



कालखंड में एक परिवार पर सोनोग्राफी के लिए चार से पांच हजार रुपए निजी हॉस्पिटलों में खर्च करना पड़ता है। डायलिसिस के मरीजों के लिए तो सत्ता के नेताओं ने खूब तालियां बटोरी, बड़े-बड़े समाचार मीडिया में प्रकाशित करवा कर वाहवाही लूटी कि अब डायलिसिस के मरीजों को अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। वही डायलिसिस की मशीन को हॉस्पिटल में पहुंचे 6 माह से अधिक समय बीत गया है लेकिन अब तक मशीन शुरू तो ठीक फिट भी नहीं हो पाई। मशीन के संचालन के लिए अनुभवी कर्मचारी

की भर्ती तक नहीं की गई। ऐसे में आने वाले कुछ समय में ये सुविधा भी लोगों को मिले इसकी उम्मीद बहुत कम है।

डॉक्टर कलेक्टर के दावे भी फैल, कोई सुविधा ठीक नहीं

जिले को मिले नए कलेक्टर तुकाराम भरसट खुर एक डॉक्टर है उनके आने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि, कम से कम जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ा सुधार होगा लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। कलेक्टर साहब के

सिविल हॉस्पिटल के दौर पर डायलिसिस मशीन को दो माह में शुरू करवाने की बात कही थी लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। विकास खंड स्तर पर हुई जन सुनवाई में डायलिसिस पीड़ित मरीजों ने दुबारा ये मांग डा. कलेक्टर साहब के सामने रखी लेकिन अब तक मशीन फिट तक नहीं हुई।

अन्य सुविधाओं की स्थिति भी गंभीर है। सिविल हॉस्पिटल में आधे समय तो एक्सरा तक नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ कर्मचारी ड्यूटी टाइम के बाद मौजूद तक नहीं रहते। जिसका एक्सरा किया जाता है उसका रिपोर्ट का एक्सरा फिल्म भी मरीज को नहीं दिया जाता है। एक्सरे के बाद सिर्फ स्क्रीन का फोटो मोबाईल पर खिच कर दिया जाता है। वही किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को इंतजार करना या अन्य अस्पताल का रुख करना पड़ता है। ब्लड बैंक को ले कर भी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को खून की आवश्यकता होने पर परेशान होना पड़ता है। इमरजेंसी और आईसीयू वार्ड तो बने हुए हैं, लाखों की मशीन लगी हुई है लेकिन उनके संचालन के लिए कुशल स्टाफ तक नहीं है।

विवाद और वसूली बन चुकी है पहचान, सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं

सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में इलाज के लिए कम, विवाद और वसूली के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। पूर्व बीएमओ सुरेश कटारा और पूर्व कलेक्टर नेहा मीणा का विवाद हो या, जमीन विवाद में उलझे डॉक्टर डाबी या बार-बार डिलेवरी और मरीज के इलाज के लिए नर्सें द्वारा पैसे मांगे जाने वाली रकम के वायरल वीडियो। या सिविल हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध होने के बाद भी हॉस्पिटल के बाहर निजी मेडिकल से दवाइयां उपलब्ध होने का मामला। गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटलों में भेजने के मामले। इन सभी मामलों में सिविल हॉस्पिटल पेटलावद सबसे आगे है। ऐसे कई मामले उजागर हुए, प्रमाणित हुए लेकिन कार्रवाई नहीं।

हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टरों के अवैध शराब की दुकानों पर किए गए हड़दंग की खबरे भी आईं। हॉस्पिटल में पदस्थ ज्यादातर डॉक्टर अपने निजी क्लीनिक और हॉस्पिटलों को संचालित करने में रुचि दिखा रहे हैं और हॉस्पिटल में नाम मात्र के लिए हजरी लगाते हैं। इस प्रकार के गंभीर मामलों के सामने आने के बाद कार्रवाई के नाम पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, नतीजन आज तक हॉस्पिटल की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है।